सोनीपत में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक रोड शो के दौरान आप नेता मनीष सिसौदिया, हरियाणा पार्टी अध्यक्ष सुशील गुप्ता और राज्य पार्टी उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। कलायत से अनुराग ढांडा को मैदान में उतारा गया है.

जनहितैषी

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:29 अंक:269 दिनांक:10-09-2024 मंगलवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डलास में जो बातें रखीं हैं वो पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली हैं। रोजगार को लेकर उनकी बिजन बिलकुल क्लियर है। उन्होंने वहां बताया कि दुनिया में बेरोजगारी क्यों बढ़ी है।

रेलवे ट्रैक पर मिला सिलेंडर, पेट्रोल और बारूद, कहीं ट्रेन को उड़ाने की साजिश तो नहीं

-पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी, दो हिस्ट्रीशीटरों को भी हिरासत में लिया

कानपुर,(ईएमएस)। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश की जांच करने में पुलिस और एटीएस की टीमें जुटी हैं। इसका खुलासा करने के लिए पुलिस की ओर से पांच टीमों का गठन किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने दो हिस्ट्रीशीटरों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

बता दें भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे लाइन पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई थी, जिसके बाद ट्रेन खड़ी हो गई थी। रेलवे लाइन पर सिलेंडर आखिर किसने रखा था। इसकी पुलिस जांच कर रही है। जो मिठाई के डिब्बे में पेट्रोल और बारूद बरामद किया था और जहां से माचिस मिली है, उसकी भी जांच की जा रही है। इसकी जांच के लिए एक टीम गठित की गई है।

पुलिस ने बताया कि 8 सितंबर रात को अनवरगंज-कासगंज रेलवे लाइन पर बर्राजपुर और बिल्हौर के बीच कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे भरे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई।

लोको पायलट ने बताया कि उसे ट्रैक पर कोई संदिग्ध चीज दिखाई दी जिसके बाद उसने ब्रेक लगाया, लेकिन उसके बाद भी ट्रेन पर काबू नहीं किया जा सका और ट्रेन उससे टकरा गई, जिसके बाद तेज आवाज हुई। लोको पायलट के मुताबिक, इस घटना के बाद ट्रेन को रोक दिया और गार्ड समेत अन्य अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी गई।

जानकारी मिलते ही रेलवे अधीक्षक, आरपीएफ और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जांच की गई तो झाड़ियों में पुलिस को एलजीपी का एक सिलेंडर, मिठाई के डिब्बे में पेट्रोल की बोतल और बारूद के साथ माचिस जैसे कई घातक पदार्थ मिले। ट्रेन को आधा घंटा रोकने के बाद रवाना कर दिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने जांच पड़ताल की। सभी संदिग्ध वस्तुओं को जांच के लिए भेज दिया गया है।

वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि जिस तरह से रेलवे को लगातार अराजक तत्वों द्वारा निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, वह ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर रेल दुर्घटना करवाने की कोशिश की गई है। वंदे भारत पर पत्थरबाजी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। मैं जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं कि सुरक्षा एजेंसी और पुलिस इस पर नजर रख रही हैं और ऐसे देश विरोधी अराजक तत्वों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त एक्शन लेगी।

बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसमी सिस्टम से भारत के कई राज्यों में होगी भारी बारिश

नई दिल्ली (ईएमएस)। बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसमी सिस्टम से भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि डिप्रेशन पुरी से लगभग 150 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व, गोपालपुर से 180 किमी पूर्व-दक्षिण पूर्व, पारादीप से 190 किमी दक्षिण, चांदबाली से 250 किमी दक्षिण, आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से 240 किमी पूर्व और पश्चिम बंगाल के दीघा से 350 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में है।

आईएमडी ने एक बुलेटिन में कहा कि पुरी और दीघा के बीच तटों को पार करने के बाद इसके अगले दो दिन में झारखंड और उससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसके चलते ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा में कई स्थानों पर अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है।

बंगाल के दक्षिणी हिस्से के पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, दक्षिण 24 परगना, हुगली, नादिया, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिलों में 12 सितंबर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि कोलकाता और इसके आसपास हावड़ा एवं हुगली जिलों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की से मध्म बारिश होगी। झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में 10-11 सितंबर को भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।

चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगाः राहुल गांधी

टेक्सास(ईएमएस)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डलास में जो बातें रखीं हैं वो पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली हैं। रोजगार को लेकर उनकी बिजन बिलकुल क्लियर है। उन्होंने वहां बताया कि दुनिया में बेरोजगारी क्यों बढ़ी है। इस समस्या का समाधान जिसने खोज लिया है वहां बेरोजगारी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में छात्रों से कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और भारत समेत कई देशों में रोजगार बड़ी समस्या बन रहा है। वहीं चीन में बेरोजगारी की दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान ना देने की वजह से बेरोजगारी का संकट पैदा हुआ है। भारत में रोजगार देने के लिए इस सेक्टर में सुधार की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा, भारत में अधिकतर चीजें मेड इन चाइना हैं। इसीलिए चीन सफल है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया गया। इतने में बहुत सारे उद्योग खड़े हो सकते थे। उन्होंने कहा कि जब हम जनता का कर्ज माफ करते हैं तो सवाल किए जाते हैं लेकिन जब कुछ लोगों का इतना कर्ज माफ कर दिया गया तो किसी ने सवाल नहीं किया।

राहुल गांधी ने कहा, पश्चिम में रोजगार की दिक्कत है। भारत में भी बेरोजगारी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनमें बेरोजगारी नहीं है। चीन में रोजगार का संकट नहीं है। वियतनाम में भी यह परेशानी नहीं है। वहीं दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो कि रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं। अगर आप अमेरिका को ही देखें तो 1940, 50 और 60 में यह वैश्विक उत्पादन का केंद्र था। यहां कार, वॉशिंग मशीन, टीवी सभी चीजें बनाई जाती थीं। इसके बाद यह प्रोडक्शन कोरिया और जापान चला गया। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पकड़ लिया। अब चीन का वैश्विक उत्पादन में बड़ा योगदान है। भारत को भी रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना होगा। भारत यह नहीं कह सकता कि मैन्युफैक्चरिंग चीनियों के लिए है। हमें लोकतांत्रिक माहौल में प्रोडक्शन बढ़ाने पर काम करना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते, बेरोजगारी का संकट दूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और भारत में बिना मैन्युफैक्चरिंग को सुधारे बेरोजगारी का संकट दूर नहीं होगा। और हमारी राजनीति में ध्रुवीकरण भी इसी वजह से होता हैराहुल गांधी ने कहा कि भारत में कुछ लोगों को ही बड़े-बड़े प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं। एक या दो को ही पोर्ट्स और डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। इस वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग की हालत खराब हो गई है। विपक्ष की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने कहा, बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। सुनने से लोगों को बेहतर समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, विपक्ष जनता की आवाज होती है। संसद युद्धक्षेत्र की तरह होता है जहां शब्दों से लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन जरूरी है कि यह समझदारी और संवेदनशीलता के साथ हो।

विदेश से आए शख्स में मिले मंकीपॉक्स के लक्षण, अस्पताल में किया आइसोलेट

-स्वास्थ्य मंत्रालय पता लगा रहा किन-किन व्यक्ति के संपर्क में रहा मरीज

नई दिल्ली,(ईएमएस) मंकी पॉक्स जो दुनिया के कई देशों में फैल चुका है जिसे लेकर डब्ल्यूएचओ भी चेतावनी जारी कर चुका है। अब भारत में भी इसकी एंट्री हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हाल ही में एक मरीज विदेशे से भारत आया है, जो ऐसी कंट्री में था जहां पर मंकी पॉक्स की बीमारी फैली है। मंकी पॉक्स जैसे लक्षण होने के कारण मरीज को आइसोलेट कर दिया गया है। उसके सभी टेस्ट किए जा रहे हैं। मरीज को डेसिग्नटेड अस्पताल में आइसोलेट किया गया है और वर्तमान में उसकी हालत स्थिर है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप मामले को देखा जा रहा है। यह पता लगाने के कोशिश की जा रही है कि कौन-कौन उस व्यक्ति के संपर्क में आया है। मंत्रालय ने कहा ऐसे मामलों से निपटने के लिए पूरी तैयार कर रखी है और किसी भी संभावित जोखिम से निपटने के लिए मजबूत उपाय किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। साथ ही राज्यों को कोरोना वायरस की चुनौती के बीच अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पिछले दिनों हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में यह बात सामने आई थी कि मंकीपॉक्स का दो से चार सप्ताह का संक्रमण होता है और रोगी आमतौर पर सहायता संबंधी प्रबंधन से ठीक हो जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक साथ रहने और आमतौर पर यौन संबंध, शरीर, घाव के तरल पदार्थ के साथ सीधे संपर्क या संक्रमित व्यक्ति के दूषित कपड़े, चादर का इस्तेमाल करने से होता है।

बता दें डब्ल्यूएचओ ने इससे पहले जुलाई 2022 में मंकीपॉक्स को पीएचईआईसी घोषित किया था जिसके बाद मई 2023 में इसे रद्द कर दिया था। 2022 से वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूएचओ ने 116 देशों से मंकीपॉक्स के कारण 99,176 मामले और 208 मौतें होने की बात कही थी।

मणिपुर हिंसा की आंच राजभवन तक पहुंची

-ड्रोन हमलों के खिलाफ छात्रों ने किया प्रदर्शन, पथराव, 20 घायल

-सुरक्षाकर्मियों को जान बचाने भागना पड़ा

इंफाल,(ईएमएस)। मणिपुर में जारी हिंसा की आंच अब राजभवन तक पहुंच गई है। राजधानी इंफाल में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राजभवन पर पत्थरबाजी कर दी। ऐसे में सुरक्षाकर्मियों को जान बचाने यहां-वहां भागना पड़ा है। पुलिस और सुरक्षाबलों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की। वहीं कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में करीब 20 छात्र घायल हो गए।

गौरतलब है कि मैतेई समुदाय से आने वाले छात्र मणिपुर में अचानक बढ़ी हिंसक घटनाओं के खिलाफ 8 सितंबर से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में उनका साथ स्थानीय लोगों ने भी दिया है। किशमपट के टिडिम रोड पर रविवार को करीब 3 किमी तक मार्च के बाद प्रदर्शनकारी छात्र राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच गए थे। प्रदर्शनकारी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे। छात्रों की ज्ञापन सौंपने वाली मांग को सोमवार के दिन सुरक्षाबलों ने पूरी कर दी, लेकिन छात्र सड़क पर प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक वे यहीं डटे रहेंगे। इसी दौरान छात्रों की सुरक्षाबलों से झड़प भी हो गई। बैरिकेड लगाकर सुरक्षाबलों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने की कोशिश की। मामला बढ़ता देख सुरक्षाबलों ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर बुलेट का इस्तेमाल करते हुए छात्रों को तितर-बितर करने की कोशिश। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। सुरक्षाबलों की कार्रवाई में 20 छात्र घायल हुए हैं।

ड्रोन हमलों का कर रहे विरोध

प्रदर्शन कर रहे छात्र असल में ड्रोन हमलों का विरोध कर रहे थे। बतला दें कि 1 और 3 अगस्त को मैतेई इलाकों में ड्रोन हमले हुए थे। उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया है और उनसे राज्य छोड़ जाने की मांग भी की है। छात्रों ने राज्य के 60 में से 50 मैतेई विधायकों से अपना रुख स्पष्ट करने या इस्तीफा देने जैसी बात भी कही है। इन छात्रों की मांग है कि राज्य में यूनिफाइड कमांड की कमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को दी जानी चाहिए। इस आधार पर केंद्रीय और स्टेट फोर्स की कमान केंद्र की बजाय मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए। छात्र डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की भी मांग कर चुके हैं।

कुकी-मैतेई के बीच हिंसा जारी

मणिपुर में पिछले 7 दिनों में हिंसा बढ़ गई है। इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यहां बताते चलें कि मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा का दौर जारी है। हाल ही में मणिपुर में ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल हमलों के लिए किया गया, जिससे स्थिति बिगड़ गई है।

दुर्गा पूजा का समय नजदीक.....मैंने पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा देने से रोका

-सीएम ममता बनर्जी ने किया बड़ा खुलासा

कोलकाता (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते कोलकाता पुलिस कमिश्नर खुद मेरे पास आकर इस्तीफा देने की इच्छा जता रहे थे। लेकिन दुर्गा पूजा का समय नजदीक है। इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया। बता दें कि आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी के बाद से लगातार पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग उठ रही है।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक की। बैठक के बाद सीएम ममता ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान हम सभी को सतर्क रहना होगा। धर्म व्यक्तिगत है लेकिन त्यौहार सभी का है। दुर्गा पूजा हमारा सबसे बड़ा त्यौहर है। बंगाल को बदनाम करने की कोई साजिश नहीं होनी चाहिए।

ममता ने कहा कि कुछ चैनल लगातार बंगाल को बदनाम करने के लिए उकसा रहे हैं। वे बंगाल के लोगों का अपमान करने में जुटे हैं। वे भूल गए हैं कि बंगाल के लोग साल भर इस सबसे बड़े त्यौहार का इंतजार करते हैं। ममता ने कहा कि मैंने कभी भी मृत डॉक्टर के परिवार को पैसे की पेशकश नहीं की। यह मेरी बदनामी के अलावा कुछ नहीं है। बता दें कि कोलकाता कांड के बाद ममता बनर्जी चौतरफा घिर गई हैं। एक ओर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं टीएमसी के कई नेताओं ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोला है।

बीच सफर में वंदेभारत ट्रेन ने दिया धोखा

इटावा (ईएमएस)। प्रतिष्ठित वंदेभारत ट्रेन सोमवार को बीच सफर में ही धोखा दे गई। ट्रेन के इंजन में आई तकनीकी खराबी के कारण आउटर पर ट्रेन खड़ी हो गयी और आगे नहीं बढ़ पायी। वंदेभारत ट्रेन में अन्य यात्रियों समेत राज्यसभा सांसद गीता शाक्य सफर कर रहीं है। करीब एक घंटे तक ट्रैक बाधित रहा। इस बीच छह एक्सप्रेस ट्रेन लेट हुई, वहीं दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग बाधित रहा। वंदे भारत के यात्रियों को दो घंटे बाद दूसरी ट्रेन से किसी तरह मान मनौव्वल के बाद कानपुर की ओर रवाना किया गया। उधर, भरथना रेलवे स्टेशन के बीच आउटर पर खड़ी वंदे भारत का मरम्मत कार्य के लिए रेलवे की टेक्निकल टीम व अधिकारी मौके पर पहुंचे।

हरियाणा में आप-कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ

-आप ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की

चंडीगढ़,(ईएमएस)। कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने की सूरत में हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अकेले विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बनाया है। इसके चलते आप ने सोमवार को दोपहर बाद 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है।

आप द्वारा जारी लिस्ट से साफ हो गया है कि अब वह इस चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन के बगैर ही चुनाव मैदान में उतरेगी। इससे पहले आप के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा था कि यदि आज भी बात नहीं बनती है तो पार्टी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन न होने की बड़ी वजह सीट शेयरिंग को माना जा रहा है। यहां बतलाते चलें कि आप ने कांग्रेस से 10 सीटें मांगीं थीं। यह सीटें पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर वाले जिलों में आती हैं। आप ने तर्क दिया था कि दोनों जगह उनकी सरकार है, इसलिए उनके प्रत्याशियों को लाभ होगा। जबकि कांग्रेस सिर्फ 5 सीट देने को तैयार थी। ऐसे में कांग्रेस ने आप की दिल्ली-पंजाब बार्डर इलाकों वाली सीटों की मांग को भी दरकिनार कर दिया और उसे शहरी क्षेत्रों से चुनाव लड़ने को कहा। गौरतलब है कि प्रदेश की कुल 90 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे।

राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह... एक गद्दार संघ को नहीं समझ सकता

नई दिल्ली (ईएमएस)। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल सोमवार को अमेरिका के टेक्सास में कार्यकम के दौरान राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर तंज करते बयान दिया था। इसके जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा, एक गद्दार आरएसएस को नहीं समझ सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि संघ मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है।

राहुल गांधी ने संघ की आलोचना कर कहा, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लोकसभा चुनाव के समय साफ हो गई, जब लाखों भारतीयों को एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे है।

राहुल गांधी की आलोचना का जवाब देकर केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि अगर उनकी दादी से आरएसएस की भूमिका के बारे में पूछने की कोई तकनीक है, तब उन्हें ऐसा करना चाहिए या इतिहास के पन्नों में झांकना चाहिए। संघ को सही मायने में समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्मों की जरूरत होगी। एक देशद्रोही आरएसएस को नहीं समझ सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी केवल भारत को बदनाम करने के लिए विदेश यात्रा करते हैं। वे इस जिंदगी में कभी भी संघ को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह भारत के मूल्यों और संस्कृति में निहित है।

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा द्वारा राहुल गांधी की तारीफ करने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी उच्च शिक्षा, व्यापक अध्ययन और रणनीतिक सोच की वजह से उन्हें समझना आसान नहीं है। पित्रोदा का बयान तब आया, जब वे टेक्सास में भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे, जहां राहुल गांधी दौरे पर हैं। मालवीय ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा, कभी-कभी राहुल गांधी को समझना आसान नहीं होता है, उनके गुरु पित्रोदा कहते हैं। उनकी गलतियां ऐसी होती हैं, जिससे ब्लूपर्स बनते हैं। पित्रोदा ने कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नजरिया बीजेपी के नजरिए के विपरीत है और वह पप्पू नहीं हैं।

तूफान से मरने वालों की संख्या हुई 59, बाढ़ के पानी में बही बस

हनोई (ईएमएस)। उत्तरी वियतनाम में तूफान के कारण हुई अधिक बारिश के चलते सोमवार को बाढ़ आ गई, जिसमें एक पुल टूट गया और एक बस बह गई। इस प्राकृतिक आपदा में 59 लोगों की जान जा चुकी है।

उत्तरी वियतनाम में कई नदियों का जल स्तर खतरनाक स्तर पर है। सोमवार सुबह पहाड़ी काओ बांग प्रांत में भूस्खलन के कारण 20 लोगों को ले जा रही एक यात्री बस बाढ़ के पानी में बह गई, जिसके बाद बचाव दल को तैनात किया गया, लेकिन भूस्खलन के कारण घटनास्थल तक जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। फु थो प्रांत में सोमवार सुबह एक स्टील का पुल ध्वस्त हो गया, जिसके बाद बचाव अभियान जारी है। खबरों के अनुसार 10 कार और ट्रक तथा दो मोटसाइकिल नदी में गिर गईं। तीन लोगों को नदी से बाहर निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन 13 अन्य लापता हैं।

2,000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन 18 प्रतिशत जीएसटी मामला फिटमेंट कमेटी के पास

नई दिल्ली (ईएमएस)। जीएसटी काउंसिल की बैठक सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बीच सबसे अधिक चर्चा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने को लेकर ऐलान पर थी। लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मामले को फिलहाल फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल हुए उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 54वीं जीएसटी मीटिंग में छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाए जाने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर पेमेंट एग्रीगेटर्स पर ये टैक्स लगाने पर चर्चा की गई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, जिसके बाद इस मुद्दे को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है, अब कमेटी इस मुद्दे को लेकर गहन विचार करने के बाद काउंसिल को रिपोर्ट देगी।

दरअसल, 2000 रुपये से कम मूल्य के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव में ये तर्क दिया गया था कि पेमेंट्स एग्रीगेटर ट्रांजैक्शंस के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और इसलिए उन्हें बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। मतलब फिटमेंट पैनल इन पर जीएसटी लगाने के पक्ष में है। बता दें कि फिलहाल, पेमेंट्स एग्रीगेटर्स को 2,000 रुपये से कम की राशि के लेन-देन पर जीएसटी से छूट दी गई है।

भारत में कुल डिजिटल पेमेंट्स में से 80 फीसदी से ज्यादा ट्रांजैक्शंस न 2,000 रुपये से कम मूल्य का होता हैं। 2016 में की गई नोटबंदी के दौरान सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पेमेंट्स एग्रीगेटर्स को लेनदेन पर व्यापारियों को दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स लगाने से रोका गया था। एग्रीगेटर अभी व्यापारियों से प्रति ट्रांजैक्शन 0.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक शुल्क वसूलते हैं। इसके बाद अगर इन छोटे पेमेंट्स पर जीएसटी लागू होता है,

झूठे हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी जेल विभाग के प्रमुख सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी जेल विभाग के प्रमुख सचिव को झूठे हलफनामे अवमानना नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सचिव से पूछा है कि प्रमुख सचिव के मार्फ़त दाखिल झूठे हलफनामे के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए? साथ ही यूपी सरकार के मुख्य सचिव को भी इस मामले मे अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पिछले तीन बार से सचिव झूठ बोल रहे हैं। हमने सोचा था कि प्रमुख सचिव इस बार सही जानकारी देंगे लेकिन उनके जवाब मे विरोधाभास है। अब हम सब कुछ देखेंगे।

कोर्ट ने सुनवाई मे मौजूद सचिव से कहा आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपने अदालत की अवमानना की है कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यूपी जेल विभाग के प्रमुख सचिव श्री राकेश कुमार सिंह के हलफनामे और पूर्व के हलफनामों में विरोधाभास है।इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसने झूठा हलफनामा दायर किया है।

हम अधिकारी को नोटिस जारी करते हैं कि झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

कोर्ट ने कहा भले ही आपका ट्रांसफ़र हो गया हो लेकिन हम आपके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने यह बात तब कहीं जब यूपी के पेश एएजी ने बताया कि यूपी जेल प्रशासन और सुधार के प्रधान सचिव तबादला कर दिया गया है और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

राम रहीम को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली (ईएमएस)। 2002 के रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को नोटिस दिया है।

इस मामले में सीबीआई ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसी साल मई में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। रणजीत सिंह की हत्या के केस में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने चार अन्य आरोपियों को भी बरी किया था।

इस हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

22 साल पहले 10 जुलाई 2002 को सिरसा डेरे के प्रबंधक रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच 2003 में सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

जनगणना कराने में देरी पर सवाल उठाने वाली एससीओएस भंग

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने जनगणना कराने में देरी पर सवाल उठाने पर सांख्यिकी पर 14 सदस्यीय स्थायी समिति (एससीओएस) को भंग कर दिया है। इस समिति की अध्यक्षता ने-माने अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रणब सेन कर रहे थे।

केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की महानिदेशक गीता सिंह राठौर के सदस्यों को भेजे गए एक ईमेल के अनुसार, समिति को भंग करने का कारण यह है कि इसका काम हाल ही में गठित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संचालन समिति के काम के साथ टकरा रहा था।

वहीं समिति प्रमुख सेन ने कहा कि सदस्यों को समिति को भंग करने का कोई कारण नहीं बताया गया। सेन ने आगे कहा कि समिति की बैठकों में सदस्यों ने सवाल उठाया था कि जनगणना अभी तक क्यों नहीं की गई है।

जुलाई 2023 में गठित समिति से उम्मीद की जा रही थी कि वह सर्वेक्षण पद्धति पर केंद्र सरकार को सलाह देगी, जिसमें सर्वेक्षण प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलू शामिल होंगे। ज्ञात रहे कि जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, वो भी तब जब कई विशेषज्ञ कह चुके हैं कि जनसंख्या के नए आंकड़ों की अनुपस्थिति में सरकारी योजनाओं और नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है।

बता दें कि भारत की दशकीय जनगणना 1870 के दशक से हर दस साल में आयोजित की जाती रही है। आखिरी जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी। अगली जनगणना, जो 2021 के लिए निर्धारित थी, शुरुआत में कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गई थी, और अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है।

सदस्यों को लिखे अपने पत्र में राठौर ने कहा कि मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के लिए संचालन समिति का गठन किया था, ताकि एनएसएसओ के सर्वेक्षण संबंधी मुद्दों पर गौर किया जा सके। पत्र में उन्होंने कहा, 'संचालन समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सांख्यिकी पर स्थायी समिति (एससीओएस) के साथ ओवरलैप हो रही हैं, जैसा कि संबंधित संदर्भ शर्तों (टीओआर) में उल्लिखित है। इस संदर्भ में, मैं यह बताना चाहूंगी कि मंत्रालय ने 13 जुलाई 2023 के अपने आदेश के तहत गठित एससीओएस को भंग करने का फैसला किया है।'

विपक्ष ने केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पूछा कि समिति को क्यों भंग किया गया? इसका जवाब भी स्वयं उन्होंने देते हुए लिखा, 'सरकार से बार-बार यह पूछने के लिए कि 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना अभी तक क्यों नहीं कराई गई है।'

जन हितैषी

भारतीय अर्थव्यवस्था की हकीकत, आर्थिक संकट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मासिक रिपोर्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उजागर किया है। सरकार द्वारा चमचमाते विकास और सफलता की कथा कहानियों का सच ओर उसके पीछे छिपी वास्तविकता का काला सच सामने आ गया है। रिपोर्ट से पता चलता है, देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। समाज के सभी वर्गों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। मध्यम वर्ग में बिकने वाली कारों की बिक्री में भारी गिरावट आई है।

रिपोर्ट में कारों की बिक्री में तेज गिरावट को लेकर चिंता प्रकट की गई है। पिछले कई महीनों में कारों की वेटिंग लिस्ट खत्म हो चुकी है। अब कारें सीधे बाजार में उपलब्ध हैं। 8 लाख से ज्यादा कारें डीलरों के पास स्टॉक में है। भारी डिस्काउंट के बाद भी कारों के खरीददार नहीं हैं। कंपनियों ने डीलरों के लिए 60 दिन की लिमिट को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है। जिसका सीधा अर्थ है कि मांग में भारी कमी है। अगस्त के महीने में कारों की बिक्री में 8 फीसदी की गिरावट आ गई है। यह गिरावट ऐसे समय में आई है। जब त्योहारों का सीजन था। आने वाले महीनो में स्थिति ओर भी खराब होगी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है, यह स्थिति उपभोक्ताओं की घटती क्रय शक्ति का नतीजा है। लोगों के पास नई कार खरीदने के लिए मार्जिन मनी के रूप में भी पैसे नही हैं। उन्हें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। उच्च ब्याज दरें और बढ़ती महंगाई घटती आय इसके प्रमुख कारण हैं। जिसके चलते लोग अब कर्ज लेने से बच रहे हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कार का उत्पादन बंद कर दिया है। जिसके कारण छटनी का खतरा भी पैदा हो गया है। लोगों की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है। उन्हें सोना गिरवी रखकर लोन लेना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 39 फीसदी की व्रद्धि हुई है। यह आर्थिक संकट की वास्तविक स्थिति को बताता है। सोना भारतीय समाज में एक सामाजिक सुरक्षा के रूप में महिलाओं के पास रखा जाता है। अब लोगों को सोना गिरवी रखकर चिकित्सा खर्च, बच्चों की शिक्षा और घर-गृहस्थी के अन्य खर्चों के लिए सोना गिरवी रखकर अथवा बेचकर काम चलाना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, सोना गिरवी रखकर कर्ज की कुल राशि 1,30,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। जो एक गंभीर आर्थिक संकट का संकेत है। क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वालों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ रही है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में चिंताजनक तथ्य यह है, क्रेडिट कार्ड के लोन पर 122ज्ञ की वृद्धि हुई है। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर क्रेडिट कार्ड एवं अन्य माध्यमों से कर्ज का सहारा ले रहे हैं। बच्चों की फीस, दवाइयों के खर्च, और घर के अन्य जरूरी सामानों के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, जीएसटी की उच्च दरें आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं। इससे महंगाई बढ़ रही है। लोगों के पास जरूरी खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। सीमेंट, स्टील, और ऑटोमोबाइल पर 28 फीसदी जीएसटी वसूल किया जा रहा है। खाने पीने की चीजों और अन्य सेवाओं पर 18 फ़ीसदी से जीएसटी वसूल किया जा रहा है। इससे मध्यम वर्ग ओर निम्न आय वर्ग के लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। आरबीआई की इस रिपोर्ट ने भारत की अर्थव्यवस्था, सरकारी दावों एवं नारों की चमक-धमक की कलई खोल दी है। वास्तव में, देश का आम आदमी आर्थिक तंगी और बढ़ते कर्ज के भँवर जाल में फंसता जा रहा है। सरकार की नीतियां गरीब और मध्यम वर्ग पर कहर ढा रही हैं। कर्ज के जाल में फंसकर आम आदमी के पास अब खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। वहीं सरकार मानती है, 84 करोड लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। यदि उनके पास पैसा नहीं होता, तो वह इंटरनेट का उपयोग कैसे करते। सरकार और भाजपा के लोग यह मानकर चलते हैं। जनता के पास बहुत पैसा है। यदि उसके पास पैसा नहीं होता तो वह सड़कों पर उतरकर विरोध करती है। रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट ने वास्तविक आर्थिक स्थिति का खुलासा कर दिया है। कर्ज और सोना गिरवी रखकर अथवा बेचकर कुछ समय तो आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन लंबे समय तक यह स्थिति भी नहीं रहेगी। लोगों का रोष अब खुलकर सामने आने लगा है। गरीब एवं मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। यदि उनकी क्रय शक्ति कम या खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकारी राजस्व का पहिया उल्टा घूमते हुए देरी नहीं लगेगी। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण मध्यम वर्ग एवं गरीब तेजी के साथ गरीब हो रहा है। वहीं बड़े-बड़े पूंजीपति दिन दूनी रात चौगुनी कमाई कर रहे हैं। भारत में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। समय रहते केन्द्र एवं राज्य सरकारों की बढ़ते टेक्स एवं शुल्क को लेकर नीति बदलाना पड़ेगी। अन्यथा भविष्य में इसके परिणाम बड़े घातक साबित होंगे।

जीवन से पलायन का डरावना सत्य है आत्महत्या

(विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस- 10 सितम्बर, 2024)

आत्महत्या दुनियाभर में एक गंभीर मुद्दा एवं बड़ी समस्या है। मौजूदा समय में दुनिया भर में इसके मामले खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस गंभीर विषय के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं आत्महत्या का पलायनवादी विचार छोड़ने के उद्देश्य से हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (डब्ल्यूएसपीडी) मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2024 के लिए इस दिवस की थीम 'चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड यानी 'आत्महत्या पर कथ्य बदलना' रखी गयी है। इस दिन को मनाने का खास मकसद इस बात को लोगों तक पहुंचाना है कि आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। साथ ही उन्हें यह भी बताना है कि आत्महत्या के अलावा जीवन में और भी बेहतर विकल्प हैं। इसके अलावा एक ऐसी समाज-व्यवस्था को बढ़ावा देना है जहां लोग मदद लेने में हिचहिचाए नहीं, बल्कि एक-दूसरे के सहयोग के लिये आगे आये। निश्चित रूप से खुदकुशी सबसे तकलीफदेह हालात के सामने हार जाने का नतीजा होती है और ऐसा फैसला करने वालों के भीतर वंचना का अहसास, उससे उपजे तनाव, दबाव और दुख का अंदाजा लगा पाना दूसरों के लिए मुमकिन नहीं है। आत्महत्या शब्द जीवन से पलायन का डरावना सत्य है जो दिल को दहलाता है, डराता है, खौफ पैदा करता है, दर्द देता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल आठ लाख लोग आत्महत्या करते हैं, इससे कई गुना अधिक लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं और इसका असर बहुत ज्यादा लोगों पर पड़ रहा है। इसके अलावा, यह 15 और 29 वर्ष की आयु के लोगों की मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्यु के शीर्ष 10 प्रमुख कारणों में से एक आत्महत्या है, जहां हर 11 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। भारत में प्रतिवर्ष 135,000 लोग आत्महत्या करते हैं, जो दुनिया की कुल आत्महत्याओं का 17 प्रतिशत हैं। आत्महत्या करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे बुढ़ापा, दीर्घकालिक बीमारियाँ, वित्तीय समस्याएँ, आत्महत्या का पारिवारिक इतिहास, आय में कमी, वैवाहिक अलगाव, नकारात्मक जीवन के अनुभव, विकलांगता की ओर ले जाने वाली शारीरिक बीमारी आदि। इसके अलावा, कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ आत्महत्या के बढ़ते जोखिम से जुड़ी हुई हैं, जैसे शराब की लत, अवसाद, तनाव, विकार आदि। लोग अवसाद, लाचारी और जीवन में कुछ नहीं कर पाने की हताशा के चलते भी आत्महत्या करते हैं। मौजूदा समय में दुनिया भर में आत्महत्या के मामले खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं। आत्महत्यामुक्त समाज-संरचना के लिए लंबे समय से कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आत्महत्या एक गंभीर मुद्दा है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आत्महत्या एक वैश्विक चुनौती है, जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इस दिवस के माध्यम से सरकारों, संगठनों, समुदायों और व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को आत्महत्या रोकने के लिए कदम उठाने की प्रेरणा दी जाती है।

भारतीय संदर्भ में आत्महत्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2021 में आत्महत्या करने वाली महिलाओं में गृहिणियों का अनुपात 51.5 प्रतिशत था। इस संदर्भ में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक सूची में शीर्ष पर हैं। आत्महत्या की कुल घटनाओं में लगभग 15 प्रतिशत गृहिणियों से संबंधित हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित करती है। पिछले दो दशकों में, आत्महत्या की दर 7.9 से बढ़कर 10.3 प्रति 100,000 हो गई है। 2021 की रिपोर्ट पर गौर करें तो उत्तराखंड में एक वर्ष में 717 लोगों ने आत्महत्या की। इसमें 463 महिलाएं हैं और इसका सबसे बड़ा कारण पारिवारिक समस्या है। ऐसे में मनोविज्ञानियों की सलाह है कि परिवार में सामंजस्य बनाकर ही खुशहाल जिंदगी जीना संभव है। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है जिससे की सकारात्मक सोच के साथ संघर्ष करने की सामर्थ्य पैदा हो सके। युवा वर्ग की महत्वाकांक्षा अपनी योग्यता व क्षमता से अधिक हो चुकी है। परिवार पर नियंत्रण नहीं है और न ही सामंजस्य रह गया है। तनाव सहने की क्षमता नहीं है। असफलता का डर और पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति को पूरी तरह प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह आत्महत्याएं हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 36 प्रतिशत लोग गंभीर अवसाद से ग्रस्त हैं इसलिए हमें सबसे पहले अवसाद को दूर करना होगा। आर्थिक संपन्नता के साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर जोर देना होगा। वहीं जिस तरह किशोरों में पढ़ाई के दबाव से आत्महत्या के मामले बढ़ गए हैं। इसे लेकर भी अभिभावकों से लेकर समाज को नए सिरे विचार करना होगा। बच्चों को शुरुआत से ही उसकी पसंद के करियर के साथ जीवन के झंझावतों को झेलने के लिए भी प्रेरित करते रहना होगा। आजकल कई लोग मानसिक समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इन दिनों लोग अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से कई सारी समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं। दुनियाभर में तनाव और डिप्रेशन से कई सारे जूझ रहे हैं। यह एक तरह का गंभीर मानसिक विकार है, जिसके सही इलाज न मिलने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डिप्रेशन के शिकार कई लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं।

इधर तीन-चार दशकों में चिकित्सा विज्ञान की प्रगति से जहां बीमारियों से होने वाली मृत्यु संख्या में कमी आयी है, वहीं इस वैज्ञानिक प्रगति, भौतिकवादी जीवनशैली एवं तथाकथित विकास के बीच आत्महत्याओं की संख्या पहले से अधिक हो गई है। चिंता की बात यह भी है कि आज के सुविधाभोगी एवं प्रतिस्पर्धी जीवन ने तनाव, अवसाद, असंतुलन को बढ़ावा दिया है, अब सन्तोष धन का स्थान अंग्रेजी के मोर धन ने ले लिया है। जब सुविधावादी मनोवृत्ति, कैरियर एवं बी नम्बर वन की दौड़ सिर पर सवार होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिये साधन, सामर्थ्य एवं परिस्थितियां नहीं जुटा पाते हैं, या काम का दबाब अति हो जाता है, तब कुंठित, तनाव एवं अवसादग्रस्त व्यक्ति को अन्तिम समाधान आत्महत्या में ही दिखता है। सिनेमा में हंसता-खेलता और सार्वजनिक जीवन में लोगों का पसंदीदा बन गया कलाकार आखिर किसी दिन अचानक खुदकुशी कर लेता है। मगर किसी भी स्थिति में जीवन खो देने के बजाय हालात से लड़ना और उसका हल निकालना ही बेहतर रास्ता होता है, यह सीख कौन देगा? पर मुख्य सवाल यही रह जाता है कि आमतौर पर सभी सुविधाओं एवं समृद्धताओं के शिखर पर स्थापित एवं अपने आसपास कई स्तर पर समर्थ लोगों की दुनिया में सार्वजनिक रूप से अक्सर मजबूत दिखने के बावजूद कोई व्यक्ति भीतर से इतना कमजोर क्यों हो जाता है कि जिंदगी के उतार-चढ़ाव या झटकों को बर्दाश्त नहीं कर पाता? पर वे कौन-सी और कैसी असामान्य परिस्थितियां इन कलाकारों के सामने रही कि उन्होंने उनसे बचने या टकराने के बजाय जिंदगी की हार यानी आत्महत्या का रास्ता चुना?

जो परिवार तलाक, अलगाव, आर्थिक कलह एवं अभावों, रिश्तों के कलह के कारण टूटी हुयी स्थिति में होते हैं उनमें भी आत्महत्या की घटनाएं अधिक पायी जाती हैं। राजनैतिक उथल-पुथल और व्यापार में नुकसान, आर्थिक तंगी भी आत्महत्या का कारण बनती है। किसानों की फसल की तबाही और कर्ज की अदायगी की चिंता से हो रही आत्महत्या भी गंभीर समस्या बन गई है। कर्ज लेकर घी पीने की जीवनशैली ने भी सबकुछ दांव पर लगा दिया है। औद्योगीकरण तथा नगरीकरण में वृद्धि भी इसके कारण है। भौतिक मूल्यों के बढ़ते हुए प्रभाव ने सामाजिक सामंजस्य की नई समस्याओं को जन्म दिया है। लेकिन आत्महत्या किसी भी सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज के भाल पर एक बदनुमा दाग है, कलंक हैं। टायन्बी ने सत्य कहा हैं कि कोई भी संस्कृति आत्महत्या से मरती है, हत्या से नहीं।' आत्महत्या की इन त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियों पर नियंत्रण जरूरी है। इसके लिये जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थितियों से गुजर रहा होता है, तो उसमें आस-पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी आदि उसे उनसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। मगर हैरानी की बात है कि अब समाज अपनी यह भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहा है। इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर कारगर उपाय जुटाने की दरकार है। जिंदगी ख़ुद को सुधारने का एक मौका हर किसी को जरूर देती है, लेकिन सुसाइड तो जिंदगी ही छीन लेती है। (लेखक- -ललित गर्ग/ ईएमएस)

क्या बंगाल भी केंद्र शासित राज्य है?

मणिपुर की आग को क़ाबू न कर अपने वाले लोग कोलकाता में एक नृशंस वारदात के बाद पिछले एक महीने से बंगाल को सुलगाये हुए हैं,और अब तो बंगाल के राजयपाल ने बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी को मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाये जाने का निर्देश देकर ये भी बताने का दुस्साहस कर डाला है कि बंगाल भी अघोषित रूप से केंद्र शासित राज्य है। बंगाल के गवर्नर अपने आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर समझ बैठे हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को अब भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की मानसिक शांति के लिए अपने पद से इस्तीफा देकर विधानसभा के नए चुनाव करा देना चाहिए।

लत्ते का सांप बनाने में दक्ष भाजपा को कोलकाता की महिला चिकित्स्क के साथ बलात्कार और हत्या की वारदात के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ने का एक और बदसूरत बहाना मिल गया है। भाजपा संदेशखाली की कथित वारदातों के बाद भी ममता बनर्जी से सिंघासन खाली नहीं करा पायी। अब बलात्कार की इस नृशंस वारदात के बहाने एक बड़ा आंदोलन भी ममता को हटाने के लिए सही औजार साबित नहीं हो रहा है ,हालाँकि बंगाल के गवर्नर डॉ सीबी आनद बोस एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं ममता सरकार को अपदस्थ कराने की। उन्होंने मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं।

बोस साहब भूल जाते हैं कि वे अव्वल तो एक गवर्नर हैं ,लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। दुसरे वे सिर्फ गवर्नर हैं बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं। मंत्रिमंडल की अभियाचित बैठक बुलाने और न बुलाने का नैतिक अधिकार उन्हें है नहीं ,लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं,, क्योंकि उनकी इस कार्रवाई से उनके आका खुश हो सकते हैं। सीबी आनंद बोस अपने और अपने आकाओं की ख़ुशी के लिए पिछले दिनों में बहुत कुछ उछल-कूंद कर चुके हैं ,लेकिन वे भूल रहे हैं कि इस मामले में वे पूर्व गवर्नर जगदीप घनकड़ को छू भी नहीं सकते। बोस साहब सिर्फ राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं ,जो वे भेज चुके हैं ,लेकिन दिल्ली सरकार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का या तो साहस नहीं जुटा पा रही है या फिर उसे मालूम है की ऐसा करने से सरकार को जगहंसाई हो सकती है।

बलात्कार और हत्या जैसी जघन्य वारदातों के बाद यदि किसी चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत मानी जाये तो सबसे पहले मणिपुर को प्राथमिकता देना होगी । बाद में देश का शायद ही कोई ऐसा सूबा हो जो नारी शक्ति वंदन में अव्वल हो और वहां बलात्कार तथा हत्या जैसी जघन्य वारदातें आये दिन न हो रहीं हों। देश के दिल मध्यप्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में तो फुटपाथ पर बलात्कार के चलचित्र वायरल हो चुके हैं ,लेकिन क्या हुआ । वहां पत्ता भी नहीं खड़का,क्योंकि मप्र की मुख्यमंत्री ममता दीदी नहीं हल्की मोहन भैया हैं। डबल इंजिन की सरकार है उनकी। मेरठ में एक नाबालिग लड़की कि साथ सामूहिक बलात्कार हुआ ,लेकिन उप्र में योगी जी की सरकार है।

बलात्कार और हत्या की जघन्य वारदातें तो केवल बंगाल में अक्षम्य हैं। एक कटु सत्य ये है कि भाजपा का महाबली नेतृत्व पिछले दस साल में अपनी सारी ताकत लगाकर भी बंगाल को नहीं जीत पाया है। जीतना तो दूर ममता बनर्जी को न भयभीत कर पाया है और न झुका पाया है। उसका हार दांव उलटा ही पड़ा है । ममता बनर्जी को न ईडी ,सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह जेल भेज पायी और न नीतीश बाबू की तरह अपना समर्थक बना पायी। ममता को अपदस्थ करने के अश्वमेघ यज्ञ में जगदीप धनकड़ की आहूति भी बेकार गयी। ममता इतनी सख्तजान निकलेंगी ये भाजपा के महाबलियों ने सोचा ही न था। ममता न बैलेट से हारी और न बुलट से। ममता को बहन मायावती की तरह घेरना भी मुमकिन नहीं हुआ और ममता सीना तानकर आईएनडीआईए गठबंधन के साथ खड़ी हो गयीं।

आपको यकीन करना पडेगा कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का अपना दिवास्वप्न तो पूरा कर लिया किन्तु बंगाल जीतने का सपना अभी तक अधूरा है । ममता बनर्जी बंगाल में मुख्यमंत्री पद पर बैठकर भाजपा के महाबली नेतृत्व की छाती पर दाल दल रहीं हैं। मै भी उन लोगों में से हूँ जो ममता बनर्जी के सरकार और पार्टी चलने के तौर-तरीकों से इत्तफाक नहीं रखते ,लेकिन मै उन लोगों में भी शुमार किया जा सकता हूँ जो तानाशाही के खिलाफ बहादुरी से लड़ने का साहस दिखने के कारण ममता की सराहना करते है। भाजपा के देवीय नेतृत्व के लिए जितना आसान जम्मू-कश्मीर से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाना था उतना आसान बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी को हटा पाना नहीं है।

भाजपा बंगाल में एक हारे हुए योद्धा के रूप में नजर आ रही है । मेरी भाजपा के प्रति पूरी सहानुभूति भी है ,और मै भाजपा के महाबली नेतृत्व से गुजारिश करना चाहूंगा कि पार्टी ममता बनर्जीको अपने तय समय तक बंगाल में आसानी से राज करने दे । भाजपा के लिए बेहतर है कि वो अपनी ताकत बंगाल में ममता को अपदस्थ करने में लगाने के बजाय हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव जीतने में खर्च करे।लेकिन मुझे बचपन में कंठस्थ कराया गया वो श्लोक भी याद आता है कि -

उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये।

पय:पानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम् ?

भगवान भाजपा को सद्बुद्धि दे ताकि वो बंगाल फोबिया से मुक्त होकर देश की सेवा कर सके ,अपनी बैशाखियों को सम्हाले रह सके। देश को भाजपा की बहुत जरूरत है। भाजपा नहीं होगी तो देश को हिन्दूराष्ट्र कौन बनवाएगा ? (लेखक-राकेश अचल/ ईएमएस)

हरियाणा : बैकफ़ुट पर भाजपा

90 विधानसभा सीटों वाला हरियाणा प्रदेश आगामी 5 अक्टूबर को विधानसभा के आम चुनावों का सामना करने जा रहा है। गत वर्षों में हुये किसान आंदोलनों में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला हरियाणा, किसान आंदोलनों के बाद पहली बार विधानसभा चुनावों से रूबरू होने जा रहा है। चूंकि हरियाणा विगत दस वर्षों से भाजपा शासित राज्य रहा है इसलिये यहाँ की हरियाणा सरकार पर ही यह सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि किसान आंदोलन के दौरान राज्य सरकार किसी भी तरह से दिल्ली जाने की ग़रज़ से पंजाब से आने वाले किसानों को भी हरियाणा में प्रवेश करने से रोके और साथ ही हरियाणा -दिल्ली सीमा पर इन्हें दिल्ली प्रवेश से भी रोके। ज़ाहिर है हरियाणा की तत्कालीन खट्टर सरकार ने केंद्र की उम्मीदों पर खरा उतारते हुये ऐसा ही किया। खट्टर सरकार को राज्य की पंजाब व दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस तैनाती करनी पड़ी। किसानों पर लाठी चार्ज,आंसू गैस,वाटर केनन का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि गोलियां भी चलानी पड़ीं। इसी गोलीबारी में कई लोग घायल हुये और एक युवा किसान की हत्या भी हो गयी। परन्तु किसानों से की गयी इस ज़ोर आज़माइश के कारण भाजपा की राज्य व केंद्र सरकार को भारी किसान असंतोष का सामना भी करना पड़ा।

किसानों की नाराज़गी पिछले दिनों हुये लोकसभा 2024 के चुनाव में ही स्पष्ट हो गयी थी। क्योंकि जिस हरियाणा में 2019 में भाजपा को राज्य की सभी दस लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी वहीं इस बार 2024 के चुनाव में उसे 5 सीटें ही मिल सकीं जबकि कांग्रेस भाजपा से 5 सीटें झटकने में कामयाब रही। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव से पूर्व मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र में भी इसी मक़सद से ले जाया गया है ताकि शायद किसानों का ग़ुस्सा कुछ कम हो सके। ग़ौरतलब है कि खट्टर के मुख्यमंत्री रहते उनकी सरकार ने कई बार न केवल किसानों पर दमनात्मक कार्रवाई की थी बल्कि स्वयं खट्टर ने ही अपने समर्थकों को किसानों के विरुद्ध हिंसा करने के लिये भी भड़काया था। आज भी हरियाणा सरकार ने शंभु बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिये बैरियर बना रखे हैं जिसकी वजह से राजस्थान,कश्मीर व पंजाब की तरफ़ से दिल्ली हरियाणा व उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले वाहनों को भारी परेशानी व जाम का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले दस वर्षों की सत्ता विरोधी लहर होने के साथ ही इस बार चुनावों में भाजपा के महिला सुरक्षा के दावे और उसकी हक़ीक़त भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ख़ास तौर पर ऐसे वक़्त में जब देश का विश्व में नाम रोशन करने वाली विश्व प्रसिद्ध पहलवान विनेश फोगट और बजरंग पुनिया जैसे ओलम्पियंस कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। विनेश फोगाट को राज्य की जुलाना विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी घोषित किया गया है जबकि बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उन्हें संगठन में और भी बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है। जहाँ किसान नेता, भाजपा सांसद व कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के ख़िलाफ़ उसके नारी शोषण के विरुद्ध किये जा रहे आंदोलन में इन ओलम्पियन्स के साथ खड़े थे वहीं यह ओलम्पियन्स भी किसान आंदोलन का समर्थन करते देखे गये थे। क्योंकि यह पहलवान भी दरअसल किसान घरानों से ही आते हैं और किसानों की जायज़ मांगों से बख़ूबी वाक़िफ़ हैं। हालाँकि इन खिलाड़ियों के कांग्रेस का दामन थामने के बाद बृज भूषण सिंह ने ज़ोर शोर से यह कहना शुरू कर दिया है कि पहलवानों द्वारा उनके विरुद्ध शोषण का आरोप लगाना कांग्रेस द्वारा दो वर्ष पूर्व लिखी गयी स्क्रिप्ट का हिस्सा थी।

राज्य में भाजपा पर कांग्रेस की ज़बरदस्त बढ़त के दो और भी कारण हैं। एक तो यह कि राहुल गाँधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय की गयी भारत जोड़ो यात्रा, हरियाणा से होकर गुज़री थी। इस यात्रा ने न केवल राज्य के मतदाताओं पर अपना प्रभाव छोड़ा था बल्कि राज्य के कांग्रेस जनों में भी जोश व उत्साह का संचार किया था। जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के रूप में सामने भी आया। अब जहां कांग्रेस 5 लोकसभा सदस्यों की जीत के साथ बुलंद हौसले से चुनाव मैदान में है वहीं भाजपा जिताऊ उम्मीदवार मैदान में उतारने के चक्कर में न केवल कई दलबदलुओं को भाजपा प्रत्याशी बना रही है बल्कि परिवारवाद के विरुद्ध लंबे चौड़े प्रवचन देने के बावजूद ख़ुद भी कई परिवारवादी सूरमाओं पर दांव लगा रही है। क्योंकि भाजपा को अपने दल में योग्य व जिताऊ नेताओं की कमी महसूस हो रही है। इसी उधेड़बुन में भाजपा ने पिछले दिनों राज्य में 67 पार्टी प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की उसमें रणजीत चौटाला जैसे मंत्री सहित 9 वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिये गये। परिणाम स्वरूप भाजपा में पद व दल से नेताओं के इस्तीफ़े की झड़ी लग गयी। इस भगदड़ में कोई भाजपाई किसी दूसरे दल में टिकट के लिये ताकझांक कर रहा है तो कोई निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर अपनी भाजपा को ही उसकी औक़ात बताने के मूड में है।

वैसे भी भाजपा ने जिस समय चुनाव आयोग से पहले घोषित की गयी 1 अक्टूबर की चुनाव तिथि को टालने की मांग की थी उसी समय राज्य के लोगों को यह सन्देश चला गया था कि भाजपा चुनाव से घबरा रही है। अब 5 अक्टूबर की नई चुनाव तिथि निर्धारित होने पर भी लोगों का यही कहना है कि तिथि बदलने से लोगों की धारणा व उनका मन नहीं बदलने वाला। राज्य में भाजपा की उल्टी हवा का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि स्वयं मुख्यमंत्री नायब सैनी जो पिछली विधानसभा में नारायणगढ़ क्षेत्र से विधायक चुने गए थे उन्होंने विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होते ही अपने विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ में रोड शो आयोजित किया था । इस रोड शो का ज़बरदस्त प्रचार किया गया। फ़ोन पर भी मुख्यमंत्री नायब सैनी की आवाज़ में आम लोगों को निमंत्रण भेजा गया। परन्तु इस रोड शो में अपेक्षा से कहीं कम लोग शरीक हुये। उसके बाद ही सैनी को करनाल से चुनाव लड़ाये जाने की चर्चा चली। परन्तु जब पहली सूची सामने आयी तो पता चला कि मुख्यमंत्री नायब सैनी को पार्टी लाडवा से चुनाव लड़ा रही है। गोया मुख्यमंत्री तक को अपने लिये सुरक्षित सीट तलाश करने में मुश्किल हो रही है।

हाँ कांग्रेस को जो भी नुक़्सान हो सकता है वह पार्टी की भीतरी गुटबाज़ी से या फिर टिकट बंटवारे में बरती जाने वाली असावधानियों से। क्योंकि इस समय राज्य की कई विधानसभा सीटें ऐसे भी हैं जहाँ सौ सौ पार्टी नेता टिकट के लिये दावे पेश कर रहे हैं। कांग्रेस का ऊँचा ग्राफ़ देखकर अनेक दलबदलू भी कांग्रेस में ही पनाह ले रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस स्वयं अपने ही बोझ तले तो दब सकती है परन्तु उसने भाजपा को तो बैक फ़ुट पर धकेल ही दिया है। (लेखक – तनवीर जाफ़री/ ईएमएस)

शब्द पहेली - 8124

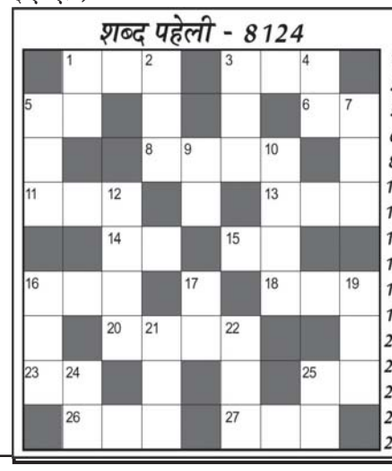

बाएँ से दाएँ

1. नियंत्रण, घोड़े की रास-3
3. ध्वज, झंडा-3
5. माहिर, होशियार-2
6. बेल, लतिका-2
8. अस्वीकृत करना-4
11. अदृश्य-3
13. फटकार, धिक्कार-3
14. अधर, होठ-2
15. सलाह, सुझाव-2
16. आश्रय-3
18. अनुमान, अंदाज-3
20. आलता, माहुर-4
23. नासिका-2
25. रहस्य-2
26. रेखा, लाइन्-3
27. परिमूल्य-3

ऊपर से नीचे

1. लाख, सौ हजार-2
2. बारीक, सूक्ष्म-3
3. तीन घंटे का समय-3
4. समय, वक्त-2
5. कोतवाल-3
7. बल, जोर, दम-3
9. श्रवणेंद्रिय-2
10. जो लायक न हो-4
12. कृष्ण के बड़े भाई-4
16. दर्पण, शीशा-3
17. नौका -2
19. आसान, सरल-3
21. उपस्थित-3
22. रस से भरा-3
24. बीता हुआ दिन-2
25. रजनी, निशा-2

शब्द पहेली -8123 का हल

	आ	र	ति		अ	ना	मि	का
आ	न		ल	जी	ज			र
ले		श	मि		र	न		तृ
ख	ल	ब	ला	ना		र	ई	स
	ग		ना		म		मा	
ख	न	न		म	नो	न	न	य
लि		ल	क		ई	ग		ती
हा			हा	फि	ज		का	म
न	स	वा	र		न	ज	ला	

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी : भारतीय टीम ने जापान को 5-1 से हराया

सुखजीत ने दागे दो गोल

हुलुनबुइर (ईएमएस)। सुखजीत सिंह के दो शानदार गोलों से भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के लीग मैच में जापान को 5-1 से हरा दिया। इस प्रकार हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में लगातार अपना दूसरा मुकाबला जीता है। भारतीय टीम ने पहले मैच में मेजबान चीन को 3-0 से हराया था।

भारत की ओर से सुखजीत ने दूसरे ही मिनट में एक गोल कर टीम को जीत दिला दी। इसके एक मिनट बाद ही अभिषेक ने एक एक गोल दागकर टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। संजय ने 17 वें मिनट में एक गोल कर बढ़त 3-0 की कर दी। इसके बाद उत्तम सिंह ने 54 वें मिनट में एक गोल दागा। सुखजीत ने इसके बाद 60वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। इस प्रकार पूरे मुकाबले में भारतीय टीम हावी रही। वहीं जापान की

शेयर बाजार बढत के साथ बंद

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार सोमवार को बढ़त पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये तेजी दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के बाद भी खरीदारी हावी रहने से आई है। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 390.05 अंक करीब 0.48 फीसदी बढ़कर 81,573.98 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 84.25 अंक तकरीबन 0.34 फीसदी बढ़कर 24,936.40 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

बीएसई सेंसेक्स में सूचीबद्ध 30 कंपनियों में से 16 शेयर बढ़कर बंद हुए। वहीं सबसे अधिक लाभ हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को हुआ। ये कारोबार के अंत में 2.95 फीसदी बढ़कर 2922.10 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर पहुंचे। इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील और लार्सन एंड टुबो के शेयर भी उछाल के साथ बंद हुए।

वहीं दूसरी ओर बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों में से 14 के शेयर गिरावट पर बंद हुए। इनमें सबसे अधिक नुकसान टेक महिंद्रा के शेयर को हुआ। इसका शेयर 2.68 फीसदी नीचे आकर 1579.95 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, पावरग्रिड, टाइटन, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सनफार्मा, मारुति सजुकी इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदाणी पोर्ट्स और भारती एयरटेल के शेयर भी गिरावट पर रहे।

वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की शुरुआत ?गिरावट के साथ हुई। नौकरियों के आंकड़े उम्मीद से कम रहने के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर चिंता खड़ी हो गई है। ?जिससे एशियाई बाजारों में गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार के 13 प्रमुख क्षेत्रों में से 11 घाटे में चल रहे थे। घरेलू स्तर पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाले छोटे और मध्यम शेयरों में लगभग 0.4 फीसदी की गिरावट आई। अमेरिका में आर्थिक मंदी की चिंताओं के बाद वॉल स्ट्रीट में गिरावट का प्रभाव सोमवार को एशिया के शेयर बाजारों पर असर पड़ा और इनमें गिरावट आई। बांड यील्ड और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि निवेशकों ने सुरक्षित स्थानों के लिए जोखिम वाली संपत्तियों में निवेश करने से परहेज किया है।

वहीं दूनिया भर के बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान के निक्केई 225, चीन के शंघाई कंपोजिट और हांगकांग के हैंगसेंग भी गिरावट पर बंद हुए। वहीं यूरोप के प्रमुख बाजारों में कारोबार के दौरान तेजी रही। दूसरी ओर अमेरिकी बाजार शुक्रवार को गिरावट पर बंद हुए थे।

सोने के भाव में आई तेजी, चांदी भी चमकी

- सोने के वायदा भाव 71,500 रुपए, चांदी 83,000 रुपए के पार

नई दिल्ली (ईएमएस)। इस सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सोने-चांदी के वायदा कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। दोनों के वायदा भाव तेजी के साथ खुले। सोमवार को सोने के वायदा भाव 71,500 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 83,000 रुपये के पार कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। सोने के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रेक्ट 78 रुपये की तेजी के साथ 71,504 रुपये के भाव पर खुला।

इस समय यह 90 रुपये की तेजी के साथ 71,516 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत भी तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रेक्ट 210 रुपये की तेजी के साथ 82,967 रुपये पर खुला। इस समय यह 293 रुपये की तेजी के साथ 83,050 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। कॉमेक्स पर सोना 2,526.50 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला।

पिछला बंद भाव 2,524.60 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 2.60 डॉलर की तेजी के साथ 2,527.20 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 28.27 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 28.18 डॉलर था। इस समय यह 0.18 डॉलर की तेजी के साथ 28.36 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मुर्गी के पंखों से बना कपड़ा और पेपर-पशमीना से10गुना ज्यादा गर्माहट

जयपुर (ईएमएस)। जयपुर निवासी राधेश अग्रहरी ने लगातार 7 साल तक रिसर्च करने के बाद चिकन फाइबर से कपड़ा और पेपर बनाने का तरीका खोजा है। उन्होंने इस तकनीकी का पेटेंट भी करा लिया है।

पोल्ट्री बेस्ट दुनिया के लिए एक समस्या बना हुआ है। जयपुर के राधेश ने 2021 में व्यावसायिक रूप से गोल्डन फ्रेदर स्टार्टअप की शुरुआत की। इस स्टार्टअप में 1200 से अधिक आदिवासी महिलाएं काम कर रही हैं। पंखों को सेनेटाइज कर धागा बनाकर कपड़ा और वेस्ट से पेपर का निर्माण किया जाता है। पंख से बने कपड़े काफी गर्म होते हैं। राधेश का कहना है, पंख से बना हुआ कपड़ा पशमीना की तुलना में 10 गुना ज्यादा गर्माहट देता है।

एक मुर्गे से 70 ग्राम पंख

एक मुर्गे में करीब 70 ग्राम पंख निकलते हैं। 1 किलो पंख से 12 फ़ीसदी कपड़ा और 88 फ़ीसदी कागज बनाया जाता है। चिकन फाइबर को 100 डिग्री भाप प्रक्रिया के साथ सेनीटाइज किया जाता है। बिना केमिकल और बिना लकड़ी के कागज तैयार किया जाता है। इससे स्थानीय रोजगार भी पैदा हो रहा है। वहीं पोल्ट्री वेस्ट को प्रोसेस करने में अभी तक वातावरण दूषित होता था। उस पर नियंत्रण होने लगा है। उल्टे कपड़े और कागज निर्माण पंखों का उपयोग किया जा रहा है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

राधेश अग्रहरी को 25 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जेपी मॉर्गन जैसी संस्था इस काम में रुचि ले रही है। 11 देशों में इस प्रक्रिया पर काम शुरू किया जा चुका है। पर्यावरण के लिए भी यह तकनीकी काफी कारगर साबित हुई है।

पेट्रोल में मिलावट को कैसे पहचानें, सिर्फ एक रुपए में कर सकते हैं चेक

नई दिल्ली (ईएमएस)। पेट्रोल में ?मिलावट है या नहीं इसे आप मात्र एक रुपए में घर पर ही पहचान सकते हैं। पेट्रोल की शुद्धता को जानने के लिए आप फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर पेट्रोल पर कुछ बूंदों को गिराने पर अगर इस पर धब्बा बन जाता है, तो पेट्रोल मिलावटी है। अगर आपके पास फिल्टर पेपर नहीं है तो आप पेट्रोल की शुद्धता की जांच ए4 पेपर की मदद से भी कर सकते हैं। यह पेपर आपको आसानी से बाजार में एक रुपये में मिल जाएगा। इस पर भी फिल्टर पेपर की तरह पेट्रोल की कुछ बूंदों को गिराएं। अगर पेपर पर धब्बा बन जाता है, तो पेट्रोल में मिलावट है। अगर फिल्टर पेपर की तरह ही ए4 पेपर की तरह ही धब्बा मुक्त रहता है, तो फिर पेट्रोल शुद्ध है। पेट्रोल के घनत्व की जांच आप हाइड्रोमीटर, विशेष थर्मामीटर और कुछ अन्य उपकरणों के जरिए कर सकते हैं। हालांकि, इस विधि द्वारा पेट्रोल की शुद्धता जांचने के लिए सुविधा सिर्फ प्रयोगशालाओं या फिर पेट्रोल पंप पर ही उपलब्ध होती है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से शुद्ध पेट्रोल का घनत्व को निर्धारित किया गया है, जो 730 से 800 के बीच है। इसके बारे में पेट्रोल पंप मशीन पर लिखा होता है। अगर पेट्रोल इसके बीच है तो वह शुद्ध है। वहीं अगर पेट्रोल की डेंसिटी 800 से ज्यादा है, तो इसका सीधा मतलब है कि पेट्रोल में मिलावट हुई है।

गूगल पर एक और मुकदमा, विज्ञापनों के एकाधिकार का मामला

मुंबई (ईएमएस)। विज्ञापनदाताओं के अब दर्शकों तक पहुंचने के लिए टिकटॉक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों या पीकॉक जैसी स्ट्रीमिंग टीवी सेवाओं की ओर रुख करने की अधिक संभावना रहती है। गूगल के सर्च इंजन को एक न्यायाधीश द्वारा अवैध एकाधिकार वाला बताए जाने के करीब एक महीने बाद प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी को उसकी विज्ञापन तकनीक को लेकर एक और मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। न्याय विभाग और राज्यों का तर्क है कि गूगल ने ऑनलाइन प्रकाशकों को विज्ञापनदाताओं से मिलाने वाली तकनीक पर एकाधिकार बनाया है और उसे कायम रखा है।सरकार ने अदालती दस्तावेजों में तर्क दिया है कि लेन-देन के खरीद और बिक्री दोनों पक्षों को लेकर सॉफ्टवेयर पर प्रभुत्व रखने से गूगल को प्रकाशकों और विज्ञापनदाताओं के बीच बिक्री के लिए दलाली करने पर एक डॉलर पर 36 सेंट तक अर्जित करने में मदद मिलती है। गूगल का कहना है कि सरकार का मामला पुराने जमाने के इंटरनेट पर आधारित है, जब डेस्कटॉप कंप्यूटर का बोलबाला था और इंटरनेट उपयोगकर्ता यूआरएल फील्ड में बड़ी सावधानी से सही-सही वर्ल्ड वाइड वेब पता टाइप करते थे। विज्ञापनदाताओं के अब दर्शकों तक पहुंचने के लिए टिकटॉक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों या पीकॉक जैसी स्ट्रीमिंग टीवी सेवाओं की ओर रुख करने की अधिक संभावना रहती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में, कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू से संचालित दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी के विभाग गूगल नेटवर्क की आय में गिरावट देखी गई है, जो 2021 में 31.7 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023 में 31.3 अरब अमेरिकी डॉलर रह गई है। गूगल नेटवर्क के तहत 'एडसेंस' और गूगल ऐड मैनेजर जैसी सेवाएं शामिल हैं, जो इस मामले के केंद्र में हैं। गूगल के एकाधिकार को लेकर यह मुकदमा वर्जीनिया के एलेक्जेंड्रिया में सोमवार को शुरू हुआ।

मोटर वाहन उद्योग का जीएसटी में 14-15 प्रतिशत योगदानः सियाम

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और अब देश में संग्रहित कुल जीएसटी में इसका योगदान 14-15 प्रतिशत है।'सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स' (सियाम) के एक अ?धिकारी ने सोमवार को यहां 64वें वार्षिक एसीएमए सत्र में कहा कि मोटर वाहन क्षेत्र देश में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, हम देश में एकत्र कुल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में करीब 14-15 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.8 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से अधिक योगदान देगा। उन्होंन कहा ?कि अग्रवाल ने कहा कि केवल वृद्धि संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी में बदलाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

दो साल में मंगल ग्रह पर लांच किया जाएगा पहला स्टारशिप मिशनः मस्क

सैन फ्रांसिस्को (ईएमएस)। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि मंगल ग्रह पर पहला अनक्रूड स्टारशिप मिशन दो साल में लांच ??किया जा सकता है। स्टारशिप दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसका उपयोग इंसानों को चंद्रमा और फिर अंत में मंगल ग्रह पर भेजने के लिए किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में टेक अरबपति ने कहा ?कि मंगल ग्रह पर पहला स्टारशिप दो साल में लॉन्च होगा। मंगल ग्रह पर लैंडिंग की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए इन्हें शामिल किया जाएगा।

अगर लैंडिंग अच्छी रही, तो मंगल ग्रह पर पहले क्रू की उड़ान उड़ान चार साल में होगी। उन्होंने आगे कहा ?कि लगभग 20 वर्षों में एक शहर बनाने का लक्ष्य है, जो खुद की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। आने वाले वर्षों में किसी ना किसी ग्रह पर मानव जीवन को शुरू करने की तैयारी भी होगी। मस्क की एयरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने पहली पूरी तरह से रियूज होने वाली रॉकेट का निर्माण किया है। इससे स्पेश मिशन पर आने वाले खर्चों में काफी कमी आएगी। मस्क ने बताया कि मंगल ग्रह पर चुनौतीपूर्ण माहौल है।

मानव के लिए स्थितियां उचित नहीं है। इसके बावजूद हम आने वाले सालों में ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं, इसके लिए हमें मौजूदा तकनीक को 10 हजार गुना बेहतर करने की जरूरत होगी। स्पेसएक्स ने हाल ही में हेवी बूस्टर के साथ अपने 400 फुट ऊंचे स्टारशिप की तीसरी परीक्षण उड़ान शुरू की है। स्टारशिप में एक विशाल बूस्टर होता है, जिसे सुपर हेवी कहा जाता है। इसमें ऊपरी हिस्से में एक अंतरिक्ष यान भी है, जिसे स्टारशिप कहा जाता है। स्पेसएक्स के सीईओ कम से कम दस लाख लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बना रहे हैं।

104 दिन लगातार काम.....एक दिन आराम, हो गई मौत

बीजिंग (ईएमएस)। चीन आज भले ही आर्थिक महाशक्ति होने का दम भरता हो, उसके पीछे की सच्चाई बहुत डरावनी है। कर्मचारियों का इस कदर शोषण किया जाता है कि उनका दम निकल जाए। ताजा मामला झेजियांग प्रांत के झोउशान से सामने आया है। यहां एक 30 साल के पेंटर के कई अंगों ने अचानक काम करना बंद कर दिया, इससे पेंटर की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 104 दिन से काम कर रहा था और बीच में सिर्फ एक छुट्टी दी गई थी।

चीनी अदालत ने कहा कि पेंटर की मौत में 20 प्रतिशत जिम्मेदारी उस कंपनी की है जो शख्स से काम करवा रही थी। कंपनी को मृतक के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पेंटर को एक न्यूमोकोकल संक्रमण हो गया था। संक्रमण बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ा कि पेंटर के श्वसन तंत्र ने काम करना बंद कर दिया। 28 मई को उसकी तबीयत बिगड़ी और 01 जून को पेंटर ने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार, पेंटर ने पिछले साल फरवरी में कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पेंटर को जनवरी तक काम करना था। अगले कुछ महीनों के दौरान, पेंटर ने हर दिन काम किया। सिर्फ 06 अप्रैल के दिन छुट्टी ली।

सामजिक सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि शुरू में पेंटर की मौत को काम से जुड़ी चोट नहीं माना गया था क्योंकि पेंटर को बीमार हुए काफी वक्त हो चुका था। लेकिन जब उसके परिवार ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तब कहा गया कि वह अपनी मर्जी से ओवरटाइम कर रहा था।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पेंटर का वर्कशेडयूल चीन के लेबर कानूनों के खिलाफ था। चीनी कानूनों के अनुसार, दिन में अधिकतम 8 घंटे और हफ्ते में औसत 44 घंटे काम कराया जा सकता है।

इमरान की रिहाई की मांग को लेकर.....सड़कों पर पीटीआई

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में एक रैली आयोजित की। कार्यकर्ता अपने नेता इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे थे। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा।

पीटीआई प्रमुख इमरान की रिहाई के लिए समर्थन हासिल करने की खातिर इस्लामाबाद में रैली कर रही थी, जो पिछले अगस्त से जेल में बंद हैं। जिला एवं सत्र अदालत द्वारा इद्दत मामले में उनकी सजा के खिलाफ अपील स्वीकार करने के बाद इमरान के जेल से रिहा होने की उम्मीद थी। हालांकि, कुछ ही समय बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने उन्हें एक नए तोशाखाना मामले में गिरफ्तार कर लिया। पिछले दो तोशखाना मामलों में उनकी सजा पहले ही निलंबित कर दी गई थी, जबकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने उन्हें सिफर मामले में भी बरी कर दिया था।

प्रदर्शन के दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। रैली की शुरुआत पार्टी नेता हम्माद अजहर द्वारा भीड़ को संबोधित करने से हुई। उन्होंने कहा कि समर्थक आज देश में कानून का शासन और संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।

उन्होंने कहा कि आज कोई भी बाधा कार्यकर्ताओं को डिगा नहीं सकती। पीटीआई नेता अली मुहम्मद खान ने इमरान की रिहाई की मांग कर अफसोस जताया कि कैसे पार्टी के नेताओं को सरकार द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। मुहम्मद ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब पाकिस्तान को बचाने के लिए हमारी पार्टी बनाने वाले इमरान खान को जेल में डाल दिया जाएगा।

खबर के अनुसार रैली के अंत में, पीटीआई समर्थक पुलिस से भिड़ गए क्योंकि पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटो और वीडियो में पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से बमबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है देश के अशांत उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान पोलियो कार्यक्रम से जुड़े कार्यकर्ताओं को ले जा रहे एक वाहन पर बमबारी की गई।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बरसी गोलियां, आठ तालिबानी लड़ाकों की मौत

इस्लामाबाद,(ईएमएस)। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भारी गोलीबारी हुई। इसमें कम से कम आठ तालिबानी लड़ाके मारे गए और 16 घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि खोस्त प्रोविंस बॉर्डर पर विगत रात 9 बजे दोनों और से गोलीबारी शुरू हुई जो चार घंटे तक चली। सीमा सुरक्षा कर्मियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मारे गए लोगों में अफगान तालिबान के दो वरिष्ठ कमांडर खलील और जान मुहम्मद शामिल हैं। पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे गए हैं इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है।

इससे पहले भी पाकिस्तान-तालिबान के बीच चार सितंबर की रात गोलाबारी हुई थी। दरअसल तालिबान सरकार पाकिस्तान से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में नई चौकियों बना रही है। यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच आए दिन झड़प होती रहती है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक काल्पनिक डूरंड रेखा अलग करती है, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान का मानना है कि ये रेखा जानबूझ कर ब्रिटिश अफसरों ने खींची थी ताकि पश्तो समुदाय का बंटवारा किया जा सके। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच इसे लेकर विवाद बना हुआ है।

कनाडा में ट्रूडो सरकार के फैसले ने बढ़ाई भारतीय छात्रों की मुश्किल

-काम के घंटे किए सीमित, किराए और अन्य खर्च कैसे होंगे पूरे

ओट्टावा,(ईएमएस)। कनाडा में भारतीयों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आवासीय संकट ने भारतीयों के लिए पहले ही कठिनाई थी। अब कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए काम के घंटे सीमित करने का फैसले किया है।

कनाडा में विदेशी छात्रों के सबसे बड़े ग्रुप के रूप में भारतीयों को इन बदलावों से दो चार होना पड़ेगा। कनाडा सरकार ने आवास और स्वास्थ्य सेवा पर बढ़ते दबाव के बाद देश में अप्रवासियों की संख्या कम करने का फैसला किया है। इससे भारतीयों पर आर्थिक संकट बढ़ जाएगा।

कनाडा सरकार के नए नियम से अंतरराष्ट्रीय छात्र सप्ताह में केवल 24 घंटे ही काम कर सकते हैं। यह पिछली 20 घंटे की सीमा से 4 सप्ताह ज्यादा है, लेकिन महामारी के दौरान सरकार ने 20 घंटे की कार्य सीमा को खत्म कर दिया था। कनाडा सिर्फ छात्रों ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह के अप्रवासन को रोकने की नीति पर काम कर रहा है। इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि कनाडा के नियमों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। वरना हमारे कार्यक्रम ऐसे आवेदकों को आकर्षित कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य यहां काम करना है न कि पढ़ाई करना।

भारत से अध्ययन करने आए कई युवा अपने किराए देने और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए कैंपस के बाहर की नौकरियां करते हैं। कोरोना महामारी के कारण काम के घंटे पर लगा बैन इस साल अप्रैल में इसे खत्म कर दिया गया।

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकांश मानक शिफ्ट होती है। इसलिए भारतीय युवा प्रति सप्ताह केवल तीन शिफ्ट में काम कर पाएंगे। कनाडा में न्यूनतम वेतन 17.36 कनाडाई डॉलर (1078 रुपये) प्रति घंटा है। इससे पता चलता है कि भारतीय युवकों की आय में कमी होगी, जिसका असर उनकी जिंदगी पर पड़ेगा। कनाडा में किराए और घरों की कमी पहले से ही छात्रों को परेशान में डालती रही है। काम पर बैन उनके लिए खर्चों को पूरा करना और भी मुश्किल कर देगा।

राहुल की मौजूदगी में सैम पित्रोदा बोले- अब वो पप्पू नहीं हैं... ठहाकों से गूंज उठा हॉल

डलास,(ईएमएस)। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका की यात्रा पर हैं। वे विभिन्न मंचों से विभिन्न मुद्दों पर बोल रहे हैं। उनके साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा भी हैं। टेक्सास में इंडियन डायसपोरा को संबोधित करते हुए पित्रोदा ने मंच से राहुल गांधी को लेकर ऐसी बात कही कि पूरा सदन तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं। खास बात यह है कि सैम पित्रोदा जब बोल रहे थे, तब उस मंच पर बगल में राहुल गांधी भी मौजूद थे।

टेक्सास में अपने संबोधन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने %प्रछ,'ष्ठछप्रङ्कढ्ढ गांधी का एजेंडा कुछ बड़े मुद्दों पर बात करने का है। उनका विजन बीजेपी से बिल्कुल अलग है, जो करोड़ों-करोड़ रुपये खर्च करके प्रचार करती है। मैं आपको बता दूं कि वो 'पप्पू' नहीं हैं। वो बहुत पढ़े-लिखे हैं और किसी भी विषय पर गहराई से सोचने वाले रणनीतिकार हैं।'सैम पित्रोदा ने कहा, 'कभी-कभी उन्हें समझना इतना आसान नहीं होता। राहुल गांधी सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं।' सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं। वह विदेशों में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। भाजपा अक्सर राहुल गांधी को पप्पू कहकर मजाक बनाती रही है। उन्होंने आगे कहा, 'पचास के दशक में जब हम स्कूल जाते थे, तो गांधीवादी विचार हमारी पढ़ाई का मूल थे। समावेश और विविधता केवल शब्द नहीं थे। यही वो चीजें थीं जिन पर हम जीते थे। और जब मैं आज अपने समाज में बदलाव देखता हूं, जो हमारे मूल सिद्धांतों पर हमला करते हैं, तो मुझे चिंता होती है। तो विचार यह है कि हमें अपने लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म, भाषा या राज्य कुछ भी हो।

बच्चों को विदेश में गोद लेने की मंजूरी देने की प्रथा बंद करेगा चीन

- पिछले 30 साल में लगभग 150,000 चीनी बच्चों को विदेश में गोद लिया गया

बीजिंग (ईएमएस)। चीन ने घोषणा की है ?कि वह बच्चों को विदेश में गोद लेने की मंजूरी देने की प्रथा बंद करेगा। इसकी वजह से मौजूदा वक्त में बच्चों को गोद लेने के लिए कोशिश कर रहे विदेशी परिवारों में असमंजस पैदा हो गया है। पिछले 30 साल में कम से कम 150,000 चीनी बच्चों को विदेश में गोद लिया गया है। इनमें से 82,000 से अधिक बच्चे अमेरिका गए हैं, जो दुनिया में कहीं और से ज्यादा संख्या है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भविष्य में चीन केवल उन विदेशी नागरिकों को चीनी बच्चों को गोद लेने की अनुमति देगा, जो उनके रिश्तेदार हैं। विदेश में चीनी बच्चों को गोद लेने पर प्रतिबंध लगाए जाने से अमेरिका में सैकड़ों परिवारों के लिए असमंजस के हालात पैदा हो गए हैं, जो मौजूदा समय में चीन से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अमेरिका अब चीन के नागरिक मंत्रालय से इस बारे में स्पष्टीकरण मांग रहा है। 1990 के दशक में चीन में विदेश में बच्चों को गोद लेने की नीति को औपचारिक रूप दिया गया था, तब से दसियों हजार बच्चों को गोद लिया गया है। जिनमें से लगभग आधे अमेरिका में माता-पिता को दिए गए हैं। चीन के बच्चों को गोद लेने वाली हस्तियों में मेग रयान और वुडी एलन भी शामिल हैं। हालांकि चीन के बच्चों को विदेश में गोद देने का प्रोग्राम कई बार आलोचनाओं के घेरे में आया है। 2013 में चीनी पुलिस ने 92 किडनैप किए गए बच्चों को बचाया और तस्करी नेटवर्क के संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि चीन की विवादों से गिरी एक-बच्चा नीति ने कई परिवारों को अपने बच्चों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस पॉलिसी को 1979 में शुरू किया गया था। जब चीन अपनी बढ़ती जनसंख्या के बारे में चिंतित था। नियमों को नहीं मानने वाले परिवारों पर जुर्माना लगाया गया और कुछ मामलों में, नौकरी भी चली गई। इससे एक ऐसी संस्कृति पैदा हो गई जिसमें लड़कियों की तुलना में लड़कों को तरजीह दी जाती है। यानी कि माता-पिता अपनी लड़कियों को छोड़ देते थे। उस समय आलोचकों ने चीन की एक-बच्चा नीति और गोद लेने के कानूनों की ओर इशारा किया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि इसने बच्चों को खरीदने के लिए एक संपन्न अंडरग्राउंड मार्केट तैयार कर दिया है। कई देशों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को गोद लेने के बारे में चिंता जाहिर की है। बहरहाल 2016 में चीन ने एक-बच्चा नीति को खत्म कर दिया। 2021 में बीजिंग ने तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति देने के लिए कानूनों में संशोधन किया।

कमला हैरिस का समर्थन करने नाटू नाटू संगीत वीडियो जारी

वाशिंगटन,(ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में कुछ महीने बचे हैं ऐसे में चुनाव अभियान जोर पकड़ रहा है।

चुनाव कैंपेन के लिए अनूठे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। भारतीय-अमेरिकी उद्यमी और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए प्रमुख फेड रेजर ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को वोट देने के लिए प्रमुख युद्ध के मैदानों में दक्षिण एशियाई लोगों को जुटाने के लिए एक संगीत वीडियो जारी किया है।

गाना, नाटू नाटू, बॉलीवुड गायिका शिबानी कश्यप द्वारा प्रस्तुत किया गया है और रितेश पारिख और उनकी रचनात्मक टीम ने निर्मित है। कमला हैरिस के लिए राष्ट्रीय वित्त समिति के सदस्य अजय जैन भूटोरिया के दिमाग की उपज है नाचो नाचो सिर्फ नहीं है एक गीत, यह एक आंदोलन है। इस अभियान का उद्देश्य युद्ध के मैदानों और प्रमुख जिलों में विविध दक्षिण एशियाई-अमेरिकी समुदाय से जुड़ना है।

4.4 मिलियन से ज्यादा भारतीय-अमेरिकी और छह मिलियन दक्षिण एशियाई लोग मतदान करने के पात्र हैं, हमारा लक्ष्य कमला हैरिस को 2024 में जीत दिलाने में मदद करना है। पारिख ने कहा कि बॉलीवुड हमेशा बाधाओं को तोड़ने और हमें एकजुट करने वाली कहानियां बताने के बारे में रहा है। हैरिस उसी दृष्टिकोण का प्रतीक हैं। लोगों को एक साथ लाना और एक ऐसे भविष्य का समर्थन करना जहां विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

भूटोरिया ने कहा कि गीत और नृत्य समुदाय की उत्सव की भावना को दर्शाती है और हैरिस को वोट देने के लिए एक मजबूत संदेश देती है। उन्होंने कहा कि 2020 में हमने दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी-अमेरिकी मूल की पहली महिला को उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर इतिहास रचा। हैरिस और उनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार टिम वाल्ज़ के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए और ज्यादा बॉलीवुड-प्रेरित संगीत वीडियो जारी करने की योजना बनाई है।

बांग्लादेश में मनमानीः शेख हसीना को भारत से लाने पर अड़े चीफ प्रॉसिक्यूटर

ढाका,(ईएमएस)। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना बीते एक माह से भारत की शरण में हैं। उधर हसीना की बापसी के लिए बांग्लादेश में अपनी ढपली अपना राग चल रहा है। कहने को मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार है लेकिन ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी देश में इस वक्त ड्राइविंग सीट पर कोई और ही बैठा है। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे है लेकिन जिस तरह की चीजें वहां हो रही है उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (आईसीटी) के नए चीफ प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम देश में एक अलग ही लाइन पकड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हसीना की गिरफ्तारी के लिए वो आईसीटी में आवेदन देंगे। ताकि उन्हें भारत से लाया जा सके।

मोहम्मद यूनुस अब तक भारत के खिलाफ कुछ भी सीधे तौर पर बोलने से बचते रहे हैं। वो पहले की तर्ज पर भारत को बांग्लादेश का एक अच्छा दोस्त बता चुके

गुजरात में 'चीनी लहसुन' मुद्दे पर विवादः मार्केट यार्ड में कल नीलामी बंद

गोंडल,9सितंबर

कुछ दिन पहले राजकोट जिले के गोंडल मार्केटिंग यार्ड में चीनी लहसुन पाए जाने पर काफी हंगामा हुआ था. देश में प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन की करीब 30 बोरियां (बैग) मंडी प्रांगण में मिलीं। घटना की सूचना मिलते ही एलसीबी, एसओजी शाखा सहित मौके पर पहुंची और यह शिकायत भी दर्ज की गई है. हालाँकि, चीनी लहसुन घुसपैठ के विरोध में कल मार्केटिंग यार्ड का संचालन बंद करने का निर्णय लिया गया है।

प्राप्त विवरण के अनुसार, 7 सितंबर को गोंडल मार्केटिंग यार्ड में चीनी लहसुन आयात करने का प्रयास किया गया था. देश में प्रतिबंधित लहसुन के आयात के विरोध में गोंडल सहित सौराष्ट्र के कई बाजार प्रांगणों में लहसुन व्यापारियों द्वारा कल लहसुन की नीलामी बंद करने का निर्णय लिया गया है। मार्केटिंग यार्ड की ओर से किसानों को लहसुन लादकर नहीं आने के लिए आवेदन भी किया गया है।

गोंडल मार्केटिंग यार्ड में चीनी लहसुन की घुसपैठ को लेकर मार्केटिंग यार्ड के चेयरमैन अल्पेश ढोलारिया ने बयान दिया और कहा कि यार्ड के व्यापारियों का मानना है कि यार्ड में चीनी लहसुन घुस आया है और उन्होंने मुझे इसकी जानकारी दी. देश में प्रतिबंधित लहसुन की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हम इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन देंगे.

अहमदाबाद में भी मिलता है चीनी लहसुनः

हालांकि, इस बीच यह बात सामने आई है कि अहमदाबाद में ही चाइनीज लहसुन बेचा जा रहा है. अहमदाबाद में अवैध चीनी लहसुन को लॉरियों में खुलेआम बेचे जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि यह लहसुन कहां से आया है तो व्यापारियों ने कहा कि यह वासना एपीएमसी से लाया गया है.

संदिग्ध वायरस से लोगों में दहशत, अब तक हो चुकी है 15 लोगों की मौत

कच्छ (ईएमएस) गुजरात के कच्छ जिले में संदिग्ध वायरस से लोगों में दहशत हैं इस रोग से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी हैं कच्छ जिले के लखपत के बाद अब संदिग्ध वायरस ने अबडासा तहसील में भी दस्तक दे दी हैं जिले में संक्रमण फैलते देख स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है और गांधीनगर व राजकोट की टीमों ने प्रभावित इलाकों में जांच शुरू कर दी हैं फिलहाल डेंगू, स्वाइन फ्लू, कोंगो फिवर समेत सैंपल परीक्षण के लिए भेजा गया हैं इस संदिग्ध बीमारी से अब तक कच्छ में 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जिसमें 13 मरीज केवल कच्छ जिले की लखपत तहसील के थें राज्य सरकार ने स्वास्थ्य टीमें कच्छ भेजी हैं, जो गांव में डोर टू डोर सर्वेलंस कर रही हैं लखपत तहसील के भेखड़ गांव में बुखार के कारण तीन लोगों की मौत हुई हैं दूसरी ओर गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने कच्छ में फैल रही संदिग्ध बीमारी को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया है इस संदर्भ में उसका ध्यान आकृष्ट किए जाने के बावजूद कोई जरूरी कदम नहीं उठाए गए इस कारण कच्छ में 14 लोगों की मौत हो गई लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा और इस बारे में भी बार बार पेशकश करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई इतना ही नहीं जिम्मेदार एक भी वरिष्ठ अधिकारी ने अब तक लखपत तहसील के गांव का दौरा तक नहीं किया उन्होंने कहा कि कुशल चिकित्सकों की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जाएं और लेबोरेटरी टेस्ट किया जाए लोगों के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती शक्तिसिंह गोहिल ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से अनुरोध किया है कि वे तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में भेजकर स्थिति पर नियंत्रण पाने की दिशा में उचित कार्यवाही करें शक्तिसिंह गोहिल के बयान पर गुजरात सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का बयान सामने आया हैं ऋषिकेश पटेल ने कहा कि शक्तिसिंह का बयान तथ्यों से विपरीत हैं स्वास्थ्य विभाग पहले से कच्छ के प्रभावित क्षेतरों में कार्यरत है और सर्वे किया जा रहा हैं

पशुपालकों को 5000 हजार की सहायता देगी सरकार इन चार जिलों के पशुपालकों को लाभ मिलेगा

गांधीनगर,9 सितंबर

गुजरात की गाय-भैंस की उत्पादकता बढ़ाने और दूध उत्पादन को स्थायी तरीके से बढ़ाने के लिए, गुजरात सरकार ने रुपये प्रदान किए हैं। 5000की सहायता देने का निर्णय लिया गया है। पशुपालन मंत्री राघवजी पटेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात सरकार पशु प्रजनन के माध्यम से दूध उत्पादन में सतत वृद्धि पाने के लिए उन्नत तकनीक को पर्याप्त प्रोत्साहन दे रही है। सेक्स्ड सीमेन की खुराक की तरह, गुजरात सरकार अब भी रुपये लेती है। 5000 की सहायता दी जाएगी.

यह सहायता पायलट चरण में बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा और आनंद जिलों के किसानों को दी जाएगी ताकि किसान बड़े पैमाने पर आईवीएफ तकनीक का उपयोग कर सकें। भविष्य में इस योजना का विस्तार मांग एवं आवश्यकतानुसार अन्य जिलों में भी किया जायेगा।

पशुपालन मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए ठराष्ट्रीय गोकुल मिशनठ के तहत, आईवीएफ तकनीक के उपयोग के माध्यम से अपने मवेशियों में सफलतापूर्वक गर्भधारण करने वाले पशुपालकों को रु। के व्यय के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा 24,780 रु. 5000 की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे सबध पशुपालक जो भारत सरकार की योजना के तहत लाभान्वितहो रहे हैं, उन्हें रुपये दिये जायेंगे. साथ ही 4890 रु. 4890 की सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार के सहायता प्रदान करने के इस महत्वपूर्ण निर्णय से पशुपालक को रु. भारत सरकार, गुजरात सरकार, जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ और जीसीएमएमएफ के कुल व्यय के मुकाबले 24,780 रुपये। 19,780 को सहायता मिलेगी. परिणामस्वरूप, आईवीएफ तकनीक का उपयोग करने के लिए पशुपालक को प्रति पशु केवल रु. का भुगतान करना होगा। 5000 ही खर्च होंगे. इसके अलावा, कम आनुवंशिकी और कम दूध उत्पादन क्षमता वाले मवेशी अधिक कुशल होंगे, मंत्री श्री पटेल ने कहा।

आमतौर पर एक मादा जानवर वयस्क होने के बाद हर साल एक शावकको जन्म देती है। लेकिन इन विट्रोफर्टिलाइजेशन और भ्रूण स्थानांतरणतकनीककाउपयोग करके, उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता और उच्च दूध उत्पादन वाली मादा मवेशियों से प्रतिवर्ष लगभग12 से 20 शावक प्राप्त किए जा सकते हैं।

आईवीएफतकनीकमें ,उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाली दाता महिलाओं से बड़ी संख्या में अंडकोष प्राप्त किए जाते हैं, एक प्रायोगिक स्कूल में निषेचित किया जाता है, औरपरिणामीभ्रूण कोसामान्य प्राप्तकर्ता महिलाओं में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस विधि में, यदि लिंगयुक्त नर का उपयोग निषेचन के लिए किया जाता है, तोअधिक मादा संतानें पैदा होती हैं। अधिक दूध उत्पादन और बेहतरआनुवंशिक गुणवत्ता से पशु पालकों की आय में भी वृद्धि होगी।

गति शक्ति विश्वविद्यालय और आर्मी व वायु सेना के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

अहमदाबाद (ईएमएस) सैन्य कर्मियों को लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के मकसद से आज भारतीय सेना, वायु सेना और रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस समझौते से जहां आर्मी और एयर फोर्स को लॉजिस्टिक्स के मामले में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिलेगी, वहीं लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन यानी रसद संचालन के विभिन्न पहलुओं में क्षमता निर्माण करने और प्रभावशाली रसद प्रणाली विकसित करने मंऑ भी सहायता मिलेगी। यह समझौता पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 और राष्ट्रीय रसद नीति 2022 को भी मजबूती देने वाला साबित होगा। इसके अलावा यह समझौता भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को भी पूरा करेगा।

इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि गति शक्ति विश्वविद्यालय अत्याधुनिक लॉजिस्टिक संबंधी शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार के साथ सशस्त्र बलों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में काम करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ''इस समझौते से रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' के दृष्टिकोण के अनुरूप सशस्त्र बलों की लॉजिस्टिक्स संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक्स अब केवल सशस्त्र बलों का एक सहायक कार्य नहीं है, बल्कि यह सैन्य अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर रहा है। एक कुशल लॉजिस्टिक्स प्रणाली सुरक्षा बलों को तेजी से जुटाने और कम समय में संसाधनों को सही जगह पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन परिस्थितियों में हमारी सेनाएं काम करती हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, हमें सैनिकों, उपकरणों एवं आपूर्ति की निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता है। जानकारी, नवाचार और सहयोग के जरिए हमारी सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के नजरिए से यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।''

जाहिर है इस समझौते के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय सशस्त्र बलों के कर्मियों के नेतृत्व, प्रबंधन और संचालनात्मक अनुभव के माध्यम से, लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञों और प्रबंधकों की एक ऐसी नई पीढ़ी को आकार देने में मदद करेगा, जो आधुनिक युद्ध की बहुआयामी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस अवसर पर सीडीएस, वायुसेना प्रमुख, सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति सहित रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राजकोट के गोंडल शहर को मिले दो नए फोरलेन ब्रिज, 56.84 करोड़ के आवंटन को मंजूरी

गांधीनगर (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट जिले के गोंडल शहर में दो नए फोरलेन ब्रिज के निर्माण के लिए 56.84 करोड़ रुपए के आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इन दो नए पुलों का निर्माण स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के फ्लाईओवर ब्रिज के अंतर्गत गोंडल शहर के पांजरापोल तथा गवर्नमेंट हॉस्पिटल चौक के पास क्रमशः 28.02 करोड़ रुपए तथा 28.82 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गोंडल शहर में गोंडली नदी पर राजशाही के समय बने 100 साल से अधिक पुराने दो ब्रिज पर गोंडल और आसपास के गांवों एवं तहसील के यातायात का काफी दबाव था। 100 साल पुराने पुलों को भारी वाहनों के लिए बंद किए जाने के बाद उसके स्थान पर डायवर्जन के लिए नेशनल हाईवे 27 गोंडल से सुरेश्वर चौकड़ी तक केवल एक ही मार्ग उपलब्ध है। इतना ही नहीं, भारी बरसात के समय वियर कम कॉजवे के ओवरफ्लो होने के कारण यह रास्ता भी बंद हो जाता है, इसके चलते सभी वाहनों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष इस संदर्भ रखी गई मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने गोंडल शहर में दो नए ब्रिज बनाने के लिए 56.84 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इन दो नए पुलों के निर्माण से भावनगर-आटकोट से जूनागढ़ जाने वाले वाहनों तथा घोघावदर मोवियां से जूनागढ़ और कोटड़ा से जेतपुर-जूनागढ़ की ओर जाने वाले वाहनों को फोरलेन ब्रिज की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन दो नए पुलों के अलावा गोंडली नदी पर राजशाही काल के 100 साल से अधिक पुराने दो मौजूदा ब्रिज के नवीनीकरण के लिए भी 22.38 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति दी है। जिसके अनुसार, सेंट्रल टॉकीज से सरकारी दवाखाना तक के मौजूदा ब्रिज का 17.90 करोड़ रुपए तथा पांजरापोल के निकट स्थित सरदार ब्रिज का 4.47 करोड़ रुपए के खर्च से नवीनीकरण किया जाएगा। इन दोनों पुलों को हल्के वाहनों यानी लाइट मोटर व्हीकल के लिए चालू रखा जाएगा। वहीं, वाहन चालक भारी वाहनों तथा शहर में बाईपास यातायात के लिए नए बनने वाले दो पुलों का उपयोग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने शहरों में लोगों के 'ईज ऑफ लिविंग' यानी जीवन जीने की सुगमता में वृद्धि के साथ-साथ प्रधानमंत्री के ध्येय 'विकास भी, विरासत भी' को साकार करने के दृष्टिकोण से गोंडल में 100 साल से अधिक पुराने दो पुलों के जीर्णोद्धार तथा दो नए पुलों के निर्माण की अनुमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गोंडल की मौजूदा आबादी, आसपास के गांवों और तहसील व जिले के बाईपास तथा शहर के यातायात के साथ ही आने वाले वर्षों में विकास को ध्यान में रखते हुए इन दो नए फोरलेन ब्रिज को बनाने के दिशा-निर्देश भी दिए हैं।

राज्य में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी : पुलिस महानिदेशक

अहमदाबाद (ईएमएस) सूरत के सैयदपुरा क्षेत्र में बीती गणेश पंडाल पर हुए पथराव के बाद राज्य में गुजरात पुलिस सतर्क हो गई हैं गुजरात के पुलिस महानिदेशक विकास सहाय ने आज सभी शहरों के पुलिस आयुक्तों और जिला अधीक्षकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और कानून-व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये डीजीपी विकास सहाय ने आज प्रमुख शहरों के पुलिस आयुक्तों और सभी जिला पुलिस प्रमुखों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इसके पश्चात बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक विकास सहाय ने कहा कि आगामी ईद मिलाद 16 को है जबकि गणेश विसर्जन 17 को हैं गुजरात पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि राज्य में दोनों त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हों। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ईदे मिलाद पर राज्य में करीब 1 हजार जुलूस निकलते हैं जबकि 93 हजार गणेश स्थापना की जाती हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईदे मिलाद और गणेश विसर्जन का समन्वय किया गया है। डीजीपी कहा कि पिछले 2 दिनों में राज्य के खेड़ा जिले के कठलाल और दक्षिण गुजरात के सूरत में घटनाएं हुई हैं

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जीआईएसएफ भर्ती घोटाले में मामला दर्ज नहीं कर रही पुलिस : कांग्रेस

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात औद्योगिक सुरक्षा बल (जीआईएसएफएस) सोसायटी गुजरात सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन है और इसके अध्यक्ष गृह सचिव हैं और शासी निकाय के सदस्य आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं भले ही उन्होंने सभी सबूत दिए हैं कि अवैध भर्ती की गई हैं भर्ती नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। इसे लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश परमार ने जीआईएसएफएस के लाखों रुपये के भ्रष्टाचार की तत्काल जांच की मांग की हैं दिनेश परमार ने कहा कि जीआईएसएफएस के भर्ती घोटाले की शिकायत डीजीपी पुलिस भवन गांधीनगर को सौंपने के बावजूद शाहीबाग पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता की शिकायत सीआरपीसी-154 के अनुसार दर्ज नहीं की जा रही है। सीआरपीसी-154 के अनुसार शिकायत दर्ज नहीं करना एक अपराध है, इसके बावजूद पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा रही गुजरात में किस तरह का अन्याय है कि शिकायतकर्ता को दो साल से परेशान किया जा रहा हैं जिसकी बात ना गृह मंत्री सुनते हैं और ना गृह सचिव गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर शिकायतकर्ता को परेशान किया जाता है। किस तरह का सिस्टम चल रहा है? दिनेश परमार ने कहा कि जीआईएसएफएस कर्मचारी ने शाहीबाग पुलिस थाने में गुजरात औद्योगिक सुरक्षा बल सोसायटी के भर्ती घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ जांच करने और पुलिस मामला दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज करने की मांग की थी लेकिन शाहीबाग पुलिस स्टेशन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त, राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को शिकायतकर्ता ने एक लिखित निवेदन भी प्रस्तुत किया।

इसके बावजूद जीआईएसएफएस भर्ती घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार शिकायतकर्ता ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीआरपीसी-154 के तहत भर्ती घोटाले में मुख्य भूमिका निभानेवाले जीआईएसएफएस के सीईओ आरडी बरंडा के खिलाफ जांच करने और पुलिस शिकायत दर्ज करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। 05 जुलाई 2024 को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इस मामले पर सुनवाई की और शिकायत दर्ज करने के साथ ही जांच और कार्रवाई करने का आदेश दिया थी इसके बावजूद शाहीबाग थाने के पीआई झाला ने शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज नहीं की जीआईएसएफएस के सीईओ ने 100 से अधिक जीआईएसएफएस गार्डों को निलंबित कर दिया है। जो अवैध तरीके से होम गार्ड के फर्जी प्रमाणपत्रों से भर्ती हुए थें इसका मतलब है कि अपराध हुआ हैं इस संदर्भ में सूचना अधिकार के तहत सबूतों के साथ एक लिखित शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया गया फिर भी पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में आठ महीने तक कानूनी लड़ाई लड़ी।

गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है कि ललिता कुमारी फैसले के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इतने स्पष्ट आदेश के बावजूद और वर्ष 2013 में ललिता कुमारी के जजमेंट के आधार पर डीजीपी साहब द्वारा जारी सर्कुलर जिसमें यह भी स्पष्ट प्रावधान है कि शिकायतकर्ता की शिकायत बिना किसी जांच के दर्ज की जाती हैं बावजूद इसके अहमदाबाद शाहीबाग पुलिस स्टेशन के पीआई झाला शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज नहीं कर रहें क्योंकि जीआईएसएफएस के अधिकारी इस भर्ती घोटाले में शामिल हैं, इसलिए पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की जाती हैं

मुख्यमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र घाटलोडिया में विभिन्न सार्वजनिक गणेशोत्सव में सहभागी हुए

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र घाटलोडिया में गोता, थलतेज, बोडकदेव एवं साइंस सिटी रोड में आयोजित विभिन्न सार्वजनिक गणपति उत्सव में नगरजनों के उमंग व उल्लास में सहभागी हुए। भूपेन्द्र पटेल ने एएमसी प्लॉट साइंस सिटी, मधुवृंद सोसाइटी गणेशोत्सव, के. के. नगर पाटीदार चौक, गुरुकुल का महाराज गणेशोत्सव आदि पाँच सार्वजनिक गणेश महोत्सव के पंडालों में स्थापित गणपति प्रतिमाओं का भक्तिभाव तथा श्रद्धापूर्वक दर्शन-पूजन किया। उन्होंने गणेश महोत्सव में दर्शन करने के लिए आए नागरिकों का अभिवादन स्वीकार किया तथा बच्चों के साथ वात्सल्य भाव से वार्तालाप किया। मुख्यमंत्री ने साइंस सिटी में आयोजित सार्वजनिक गणेश महोत्सव में युवाओं व विद्यार्थियों द्वारा स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी मॉडल स्टॉल को भी रुचिपूर्वक निहारा।

वेरावल-इंदौर एवं इंदौर-गांधीधाम एक्सप्रेस आंशिक परिवर्तित मार्ग से चलेगी

अहमदाबाद (ईएमएस) पश्चिम रेलवे के सेक्शन के बीच दोहरीकरण कार्य हेतु ब्लॉक लिए जाने के कारण वेरावल-इंदौर महामना एक्सप्रेस और इंदौर-गांधीधाम एक्सप्रेस आंशिक परिवर्तित मार्ग से चलेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

11,18 और 25 सितंबर 2024 (बुधवार) को वेरावल से चलने वाली ट्रेन नं 19319 वेरावल-इंदौर महामना एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग के रास्ते चलेगी।

15, 22 और 29 सितंबर 2024 (रविवार) को इंदौर से चलने वाली ट्रेन नं 20936 एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया के रास्ते चलेगी।

ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.iâianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

आदित्य अल्ट्रा स्टील का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 09 सितंबर को खुलेगा

अहमदाबाद, 09 सितंबर, 2024: कामधेनु ब्रांड के तहत टीएमटी बार जैसे रोल्ड स्टील उत्पादों के निर्माता, आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड के 74 लाख शेयरों का एक नया इश्यू 09 सितंबर, 2024 को सदस्यता के लिए खुलेगा और 11 सितंबर, 2024 को बंद होगा। . प्रति शेयर रु. रुपये के मूल्य बैंड के साथ 10 इक्विटी शेयर। 59 से रु. 62 तय कर दिया गया है और कंपनी को एनएसई इमर्ज पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। न्यूनतम लॉट साइज 2000 शेयर होगा।

खुदरा निवेशकों के पास न्यूनतम रु. 124,000 की बोली लगानी होगी. न्यूनतम 2 लॉट (4,000 शेयर) के लिए एचएनआई रु. 248,000 की बोली लगनी है. इश्यू की बुक रनिंग लीड मैनेजर स्वस्तिका इन्वेस्टस्मार्ट लिमिटेड है और कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड इश्यू की रजिस्ट्रार है। सनफ्लावर ब्रोकिंग आदित्य बिड़ला अल्ट्रा स्टील आईपीओ की बाजार निर्माता है।

राजकोट जिला स्थित आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड 59,489 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक अत्याधुनिक टीएमटी विनिर्माण संयंत्र संचालित करता है। उन्नत तकनीक, आधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला और कर्मचारियों के लिए उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ कंपनी की उत्पादन क्षमता 108000 मीट्रिक टन है। कंपनी रिटेल लाइसेंस समझौते के तहत कामधेनु ब्रांड के तहत टीएमटी बार्स बनाती है।

कंपनी के प्रमोटर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीए सनी सुनील सिंघी ने कहा, ठकंपनी केएमआईएल के साथ अपने सहयोग का लाभ उठाती है और लोकप्रिय कामधेनु ब्रांड का उपयोग करके टीएमटी बार्स बाजार में अग्रणी स्थान हासिल किया है। कंपनी खुदरा ग्राहकों के लिए प्रीमियम टीएमटी बार में माहिर है और समय पर डिलीवरी, क्रेडिट विकल्प और अनुकूलित सेवाओं के माध्यम से मजबूत ग्राहक संबंध विकसित किए हैं। हमने इस क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद लाभप्रदता और प्रतिष्ठा बनाए रखी है। हम अपनी क्षमता को अधिक तम करने और भविष्य के विकास को समर्थन देने के लिए कार्यशील पूंजी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

एसीसी थोंडेभावी में एएसडीसी कौशल विकास के साथ अपने करियर को बदलकर ग्रामीण महिलाओं को बनाता है सशक्त

कर्नाटक, 9 सितंबर 2024: विविधतापूर्ण अदाणी पोर्टफोलियो की सीमेंट और निर्माण सामग्री कंपनी एसीसी, कर्नाटक में ग्रामीण समुदायों को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाना जारी रखे हुए है। एसीसी थोंडेभावी में अदाणी फाउंडेशन के अदाणी कौशल विकास केंद्र (एएसडीसी) ने युवाओं को उन कौशलों से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिनकी उन्हें सफल होने के लिए आवश्यकता है। हाल ही में इस एएसडीसी से चार प्रेरक सफलता की कहानियाँ सामने आई हैं, जो इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं।

शारीरिक विकलांगता और बोलने की समस्या से पीड़ित 36 वर्षीय महिला चन्नम्मा केएस को अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी करने के बाद रोजगार पाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपने किसान पिता और दिहाड़ी मजदूर भाई पर निर्भर रहने वाली सुश्री चन्नम्मा की ज़िंदगी तब बदल गई जब वह एसीसी की सीएसआर अपस्किलिंग पहल सक्षम में शामिल हुईं और एएसडीसी थोंडेभावी में दाखिला लिया। वहां तीन महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, उन्हें मराठाहल्लीमेंगूगलमेंबैक-एंड एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई, जहाँ उन्हें मुफ़्त भोजन और आवास के साथ ?15,000 मासिक आय होती थी। उन्होंने कहा, ''मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह अवसर मिलेगा,'' उन्होंने आगे कहा, ''एएसडीसी ने मुझे सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास दिया। मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि अब मैं अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकती हूं।''

मुथूट माइक्रोफिन जॉब फेयर ने पूरे भारत में पैदा किएरोजगार के अवसर

रोजगार और युवा कौशल को बढ़ावा देने के लिए 1500 से अधिक रोजगार अवसर पैदा करने का लक्ष्य

कोच्चि, 09 सितंबर, 2024: औपचारिक रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास के तहत, मुथूट माइक्रोफिन (ऍ: श्ळऊष्ध्ऊश्इ ऍ: 544055) ने 13 राज्यों में 29जगहों पर एक विशेष जॉब फेयर शुरू किया है।अग्रणी माइक्रोफाइनेंस संस्थान ने बेरोजगारी दर को कम करके और देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर, स्थानीय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में इस पहल की घोषणा की है।

मुथूट माइक्रोफिन ने बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान सहित कई प्रमुख राज्यों में सफलतापूर्वक जॉब फेयर आयोजित किए हैइन आयोजनों को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 3,000 से अधिक नौकरी चाहने वालों ने भाग लिया. इसमें उन्हें एक ही मंच पर सीधे जुड़ने और बात करने का मौक़ा मिला।

इस पहल के माध्यम से, कंपनी ने रिलेशनशिप ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर और ब्रांच क्रेडिट मैनेजर सहित संचालन में विभिन्न भूमिकाओं के लिए 1500 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने की योजना बनाई है। ये अवसर नए स्नातकों, अनुभवी पेशेवरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए खुले हैं. चयनित उम्मीदवारों को उसी दिन ऑफर लेटर प्राप्त होंगे, जिससे औपचारिक कार्यबल में उनका प्रवेश तेज़ हो जाएगा।

मुथूट माइक्रोफ़िन के सीईओ श्री सदाफ़ सईद ने कहा, ठहमारा जॉब फेयर सिर्फ़ भर्ती अभियान नहीं है. यह ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैयह 'विकसित भारत 'पहल के तहत हाल ही में पेश किए गए बजट 2024-25 की प्राथमिकताओं के अनुरूप है, जिसमें रोज़गार और कौशल पर ज़ोर दिया गया है।

गुजरात के बांध ओवरफ्लो, रिकॉर्ड तोड़ बिजली उत्पादन, 5 साल में 4600 मिलियन यूनिट

गांधीनगर ,9 सितंबर

गुजरात में बिजली उत्पादन में वृद्धि वर्तमान में पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि सरकार सौर छतों पर भी सब्सिडी दे रही है, भारत का 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित क्षमता तक पहुंचने का लक्ष्य गुजरात में जोरों पर है। सोलर रूफटॉप, जल विद्युत परियोजनाएं और नवीकरणीय ऊर्जा पार्क सहित राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। इस बीच, मानसून सीजन में गुजरात में अच्छी बारिश हुई है और गुजरात में बांधों के लबालब होने से हाइड्रो पावर स्टेशन भी रिकॉर्ड बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। जिसमें गुजरात के उकाई, कडाना, पनाम और सरदार सरोवर बांधों से अगस्त 2024 में 1067.3 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली का उत्पादन किया गया है। जबकि जुलाई में बिजली उत्पादन 308.7 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया है.

अगस्त महीने में सरदार सरोवर बांध से 800 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है. जिसमें सरदार सरोवर (आरबीपीएच) और सरदार सरोवर (सीएचपीएच) से अगस्त माह में कुल 891 एमयू बिजली का उत्पादन किया गया है. राज्य के अन्य जल विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2019 से 2024 तक राज्य में औसत जल विद्युत उत्पादन 4600 एमयू है। जिसमें उकाई, कडाना, पनाम और सरदार सरोवर बांधों से पिछले पांच वर्षों में औसतन 4600 एमयू का उत्पादन देखा गया है।

जबकि वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल जल विद्युत उत्पादन 6170.456 एमयू था, जो वर्ष 2021-22 के 2629.059 एमयू से 134 प्रतिशत अधिक है. वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल जल विद्युत उत्पादन 4584.932 एमयू है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा पर नीतियां जारी की हैं।

मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को 4.43 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मिलीं

सितंबर 9, 2024:मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (NSE - MIEL) द्वारा ऍ को हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंपनी ने अगस्त 2024 में पांच परियोजनाएं हासिल कीं है, जिनका कुल